

परिवहन विशेष

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

देर आए दुरुस्त आए, तीन साल बाद खुली दिल्ली परिवहन विभाग की आंखें



संजय बाटला
नई दिल्ली। दिल्ली की जनता को संबोधित कर अपने आप पर श्रेय लेने वाली दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग क्या जनता को यह बताना पसन्द करेगा की स्क्रेप पालिसी और भारत सरकार के बजट में कब जनता को पुराने समय सीमा समाप्त कर चुके वाहनों को अधिकृत वाहन स्क्रेप डीलर से स्क्रेप करवाने पर नए वाहन खरीदने पर स्क्रेप सर्टिफिकेट पेश करने पर टैक्स में छूट मिलेगी। दिल्ली परिवहन विभाग क्या जनता को जिनके द्वारा इतने वर्षों तक अधिकृत वाहन स्क्रेप डीलर से अपने पुराने समय सीमा समाप्त कर चुके वाहन कटवा चुके हैं को नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट ना देने की अपनी मंशा साफ करेगा। जनता के लिए यह भी सुखद है की देर से ही सही पर दिल्ली परिवहन विभाग की आंखें खुल गईं और आने वाले समय में जो फायदा तीन साल पहले से जनता को मिलना चाहिए था कम से कम अब मिलना शुरू हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों के बोल "देर आए दुरुस्त आए", कहावत चरितार्थ हो गई।

आखिर कब प्रवर्तन शाखा (यातायात पुलिस, पुलिस और आरटीओ) के अधिकारी/कर्मचारी जनता को परेशान करना करेंगे बंद

जगमोहन सिंह
नई दिल्ली। ट्रैफिक वाले कुछ और दशकों तक बिना किसी कारण के लोगों को परेशान करते रहेंगे। अब सारे रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर हैं। किसी को कहीं दिखाने के लिए कोई दस्तावेज अपने साथ क्यों रखना चाहिए।
आरसी क्यों दिखाना चाहिए? वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर की सुरक्षा प्लेट का डिस्टेंस ही काफी है। यह आसानी से सत्यापित किया जा सकता है कि वाहन पंजीकृत है या नहीं। बिना आरसी के वाहन चलाना कैसे बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना है? यह 39 एमवी एक्ट का अपराध कैसे है? ऐसा बिल्कुल नहीं है?
सरकारी पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस का अलग रिकॉर्ड होता है। किसी व्यक्ति के पास वाहन चलाने का लाइसेंस है या नहीं, यह केवल सिस्टम में उसका नाम और जन्मतिथि डालकर सत्यापित किया जा सकता है। केवल पुलिसकर्मी को दिखाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को अपने साथ क्यों रखना चाहिए? 18 वर्ष से अधिक आयु के एक सक्षम व्यक्ति को सड़क पर निजी कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस क्यों लेना चाहिए, जबकि वह खुद और दूसरों के लिए समान जोखिम के साथ उसी सड़क पर साइकिल या गियरलेस बाइक ले जा सकता है? हम 70 साल पुराने लाइसेंस राज से बाहर क्यों नहीं निकल सकते?
परिवहन अभिलेख पोर्टल में बीमा अद्यतन अनिवार्य है तथा जारी या नवीनीकृत होते ही हमेशा उपलब्ध रहता है, जिसे बीमा पोर्टल में खोज कॉलम में वाहन का नंबर डालकर भी सत्यापित किया जा सकता है। पेट्रोल पंप या अन्य दुकानों पर लाइसेंसधारी विक्रेता की मशीनों द्वारा जांचे जाने पर पीयूसीसी अद्यतन हो जाता है तथा समय पर नवीनीकरण न कराने पर वाहन स्वामी को समाप्त की चेतावनी या पीयूसीसी नवीनीकरण के लिए चेतावनी का संदेश भेजा जाता है। हालांकि पीयूसीसी दस्तावेज किसी काम का नहीं है तथा यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दस्तावेज नहीं है, जो आरंभ में लागू हुआ था, लेकिन गलत तरीके से इसकी व्याख्या कर अवैध रूप से राजस्व अर्जित करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। दायित्व तभी उत्पन्न होता है, जब वाहन सड़क पर चलते समय पीएमवीआई द्वारा जांचे जाने पर प्रदूषण फैलाता हुआ पाया जाता है। वाहन को केवल पीयूसीसी जांच केंद्र से प्रदूषण उत्सर्जन के लिए जांच करवाने तथा नोटिस के 15 दिनों के भीतर पीयूसीसी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है। पीयूसीसी की तिथि समाप्त हो जाना चालान करने तथा जुर्माना लगाने का आधार नहीं है। आजकल ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जा रहा लगभग हर काम राज्य या उसके कर्मचारियों के लिए जबर्न वसूली का नाटक मात्र है। खराब ट्रैफिक और सड़क प्रबंधन को बड़ी संख्या में चालान जारी करने के रंग में रंगना गलत है। अधिक चालान का मतलब है अधिक ट्रैफिक कुप्रबंधन और नियमों का उल्लंघन। हर व्यवस्था को प्रबंधन और सड़क की स्थिति में बेमेल के रूप में देखा जाता है। हम नागरिकों को नहीं पता कि इस डिजिटल युग में हम अशिक्षित विनियमन, विनियमन और कानून की ऐसी खराब व्यवस्था से कब छुटकारा पाएंगे। सब कुछ सत्यापित करने के लिए उंगलियों की नोक पर है, लेकिन नागरिकों पर विश्वास नहीं किया जाता है और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वे भारत के नागरिक ही नहीं हैं। हर भारतीय पर उल्लंघनकर्ता और कानून तोड़ने का संदेह या ब्रांड लगाया जाता है, जबकि केवल कुछ ही जानबूझकर उल्लंघन करने की मनोवैज्ञानिक स्थितियों के तहत कानून से बच निकलते हैं। लेकिन इस तरह के छोटे-मोटे बच निकलने से राज्य के खजाने पर कोई असर नहीं पड़ता। केवल नागरिकों में आत्म अनुशासन और सड़कों का उपयोग करने के बारे में उनकी शिक्षा का अद्यतन ही अब बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। कुपया अपने विचार खुलकर साझा करें।

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि माडल भारत सरकार में ग्रह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय से मिला

परिवहन विशेष न्यूज
नई दिल्ली। टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ग्रह मंत्री को बताया की हाइवे पर आज कल काफी लूट पाट होती रहती है और महिलाओं की सुरक्षा का खतरा भी बढ़ गया है। हाइवे पर बदमाश ओवरटेक करके गाड़ियों को लूट रहे हैं क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों की स्पीड अधिक और टूरिस्ट टैक्सी बसों की स्पीड कम है।
व्यावसायिक सवारी वाहनों की गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे और प्राइवेट वाहनों की गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा नोटिफाइड करी हुई है। टैक्सी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने ग्रह मंत्री को बताया हम एक्सप्रेस वे/हाइवे पर वाहनों को चलाने के एवज में सरकार को राजस्व के रूप में करोड़ों रुपए टोल टैक्स के नाम पर देते हैं। साथ ही बताया की दिल्ली में इंटरपोल के सम्मेलन में आये हुए अधिकारियों ने आगरा जाते हुए ड्राइवर द्वारा धीमी गति से टूरिस्ट टैक्सी चलाने की शिकायत के साथ नाराजगी भी जताई थी क्योंकि टूरिस्ट टैक्सी की गति सीमा अन्य प्राइवेट वाहनों से कम थी। आगे बताया की हमारे वाहनों में देश विदेश के सैलानी सफर करते हैं और गति सीमा की पाबंदी के कारण अगर गलती से भी किसी भी तरह की कोई दुर्घटना/लूट पाट/बलात्कार स्पीड गवर्नर की वजह से होती है तो इसकी जिम्मेदारी किस की और किस विभाग के अधिकारी की होंगी तय करना आवश्यक है।
टैक्सी एसोसिएशन ने स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता को आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से तुरंत हटवाने का आग्रह राज्य मंत्री से किया तथा बताया की स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने का आदेश सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन नियम के प्रावधान में किया गया है, इस बारे में एसोसिएशन द्वारा परिवहन मंत्री से काफी बार मिले हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। एसोसिएशन का कहना है की यह मुद्दा महिलाओं और देश विदेश के पर्यटकों की जान माल और सुरक्षा से संबंधित है पर दिल्ली और केंद्र सरकार परिवहन विभाग दोनों ने आज तक गंभीरता से नहीं लिया। *एसोसिएशन का कहना है की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी बसों की टैक्सी बसों पर स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने को गलत बताया और उन्होंने भी माना की ये स्पीड लिमिट डिवाइस (स्पीड गवर्नर) शहर के अंदर चलने वाले वाहनों के लिए तो सही है परन्तु एक्सप्रेस वे और हाइवे पर चलने वाले टूरिस्ट टैक्सी बसों को 80 किलोमीटर की स्पीड पर बांधना सही नहीं है और वह इस बात की नितिन गडकरी को पत्र लिख कर इसका समाधान करवाएंगे।

हिंडन एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी लखनऊ-इलाहाबाद के लिए उड़ान, एयरपोर्ट प्रबंधन ने कई एयरलाइंस से की बात

परिवहन विशेष न्यूज
नई दिल्ली। टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ग्रह मंत्री को बताया की हाइवे पर आज कल काफी लूट पाट होती रहती है और महिलाओं की सुरक्षा का खतरा भी बढ़ गया है। हाइवे पर बदमाश ओवरटेक करके गाड़ियों को लूट रहे हैं क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों की स्पीड अधिक और टूरिस्ट टैक्सी बसों की स्पीड कम है।
व्यावसायिक सवारी वाहनों की गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे और प्राइवेट वाहनों की गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा नोटिफाइड करी हुई है। टैक्सी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने ग्रह मंत्री को बताया हम एक्सप्रेस वे/हाइवे पर वाहनों को चलाने के एवज में सरकार को राजस्व के रूप में करोड़ों रुपए टोल टैक्स के नाम पर देते हैं। साथ ही बताया की दिल्ली में इंटरपोल के सम्मेलन में आये हुए अधिकारियों ने आगरा जाते हुए ड्राइवर द्वारा धीमी गति से टूरिस्ट टैक्सी चलाने की शिकायत के साथ नाराजगी भी जताई थी क्योंकि टूरिस्ट टैक्सी की गति सीमा अन्य प्राइवेट वाहनों से कम थी। आगे बताया की हमारे वाहनों में देश विदेश के सैलानी सफर करते हैं और गति सीमा की पाबंदी के कारण अगर गलती से भी किसी भी तरह की कोई दुर्घटना/लूट पाट/बलात्कार स्पीड गवर्नर की वजह से होती है तो इसकी जिम्मेदारी किस की और किस विभाग के अधिकारी की होंगी तय करना आवश्यक है।
टैक्सी एसोसिएशन ने स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता को आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से तुरंत हटवाने का आग्रह राज्य मंत्री से किया तथा बताया की स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने का आदेश सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन नियम के प्रावधान में किया गया है, इस बारे में एसोसिएशन द्वारा परिवहन मंत्री से काफी बार मिले हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। एसोसिएशन का कहना है की यह मुद्दा महिलाओं और देश विदेश के पर्यटकों की जान माल और सुरक्षा से संबंधित है पर दिल्ली और केंद्र सरकार परिवहन विभाग दोनों ने आज तक गंभीरता से नहीं लिया। *एसोसिएशन का कहना है की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी बसों की टैक्सी बसों पर स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने को गलत बताया और उन्होंने भी माना की ये स्पीड लिमिट डिवाइस (स्पीड गवर्नर) शहर के अंदर चलने वाले वाहनों के लिए तो सही है परन्तु एक्सप्रेस वे और हाइवे पर चलने वाले टूरिस्ट टैक्सी बसों को 80 किलोमीटर की स्पीड पर बांधना सही नहीं है और वह इस बात की नितिन गडकरी को पत्र लिख कर इसका समाधान करवाएंगे।



एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि गाजियाबाद से लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या के लिए यात्रियों की भीड़ है। इन शहरों के लिए उड़ान शुरू करने की योजना पहले से है।
हिंडन एयरपोर्ट से जल्द ही लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज के लिए उड़ानें शुरू होंगी। इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने कई एयरलाइंस कंपनियों से बात की है। एयरपोर्ट निदेशक उमेश यादव का कहना है कि जैसे ही सहमति बनती है यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी।
एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि गाजियाबाद से लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या के लिए यात्रियों की भीड़ है। इन शहरों के लिए उड़ान शुरू करने की योजना पहले से है। उमेश यादव ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से कोलकाता, बंगलुरु, गोवा के लिए उड़ान शुरू होंगी थी जिसकी तारीख अभी स्थापित कर दी गई है। वहीं, पास के शहरों के लिए उड़ान पहले शुरू करने की योजना पर प्रबंधन जोर दे रहा है।
इस संबंध में स्टार एयर, फ्लाई बिग के साथ ही अन्य कई एयरलाइंस कंपनियों से बात की गई है उन्हें एयरपोर्ट विजिट भी कराया गया है ताकि वह अपनी योजना बना सकें। एयरपोर्ट निदेशक का कहना है कि 2024 के अंत तक हिंडन एयरपोर्ट से कम से कम दस शहरों के लिए उड़ान होंगी है। वर्तमान में यहां से पांच शहरों के लिए प्रतिदिन उड़ान है।

टैम्पल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली और आसपास के इलाकों में 70 हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं, ताकि जाम से मिले छुटकारा



केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके।
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके।
दिल्ली में शुक्रवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने आगे कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन भविष्य हैं। और आखिरकार जीवशम ईंधन से होने वाले प्रदूषण की समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करेंगे।
उन्होंने कहा कि आज तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है और ज्ञान ही शक्ति है।
गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय सड़कों के निर्माण में दिल्ली में लैंडफिल से निकलने वाले कचरे का इस्तेमाल कर रहा है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि वह राजनीति से ज्यादा समाज सेवा पर ध्यान देते हैं।
गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने एलान किया कि उसने दिल्ली-एनसीआर में और उसके आसपास विभिन्न इलाकों पर मियावाकी वृक्षारोपण स्थापित करने के लिए 53 एकड़ भूमि की पहचान की है।
यह कदम नेशनल हाइवे (राष्ट्रीय राजमार्गों) को हरियाली से भरने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उठाया जा रहा है। इसके लिए, एनएचआई विभिन्न जगहों पर नेशनल हाइवे से सटे भूमि खंडों पर मियावाकी वृक्षारोपण लगाने के लिए एक अनूठी पहल करेगा।
मंत्रालय ने कहा, "राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मियावाकी वृक्षारोपण के विकास के लिए प्रस्तावित कुछ स्थलों में हरियाणा सेक्शन के द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ 4.7 एकड़ भूमि क्षेत्र, दिल्ली-वडोदरा खंड के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोहना के पास 4.1 एकड़, हरियाणा में अंबाला-कोटपूतली कॉरिडोर के राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर चाबरी और खरखड़ा इंटरचेंज दोनों मेलगण 5 एकड़ शामिल हैं।"
इसके अलावा, NH-709B पर शामली बाईपास पर 12 एकड़ से ज्यादा, गाजियाबाद के पास इस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दुहाई इंटरचेंज पर 9.2 एकड़ और NH-34 के मेरठ-नजीबाबाद खंड के पास 5.6 एकड़ भूमि की पहचान की गई है। इन चुनी हुई जगहों पर जमीनी तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं और वृक्षारोपण आगामी मानसून मौसम में किया जाएगा। इसे अगस्त 2024 के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मियावाकी वृक्षारोपण, जिसे मियावाकी पद्धति के रूप में भी जाना जाता है, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन (पारिस्थितिक बहाली) और वनीकरण विकास के लिए एक अद्वितीय जापानी दृष्टिकोण है।

इनसाइड



प्रेगनेसी में मोबाइल रीडिएशन से दूरी बनाना जरूरी वरना शिशु को हो सकता है मेटल प्रॉब्लम

अगर गर्भवती महिला के आसपास अत्यधिक मोबाइल रीडिएशन है, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। जानें, प्रेगनेसी के दौरान मोबाइल रीडिएशन से अजन्मे बच्चे के विकास में क्या समस्या आ सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हम सभी सुनते आए हैं कि अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। खासतौर पर प्रेगनेट महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है। प्रेगनेसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पेट में पल रहे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी तक हो सकती है। केवल मां ही नहीं, अगर मां के आसपास लोग वायरलेस चीजों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका भी भ्रूण में पल रहे बच्चे पर खराब असर पड़ सकता है। मॉमजंकशन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में किए गए शोध में पाया गया है कि अत्यधिक मोबाइल रीडिएशन में अगर गर्भवती मां रहती है तो जन्म के बाद बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। यही नहीं, इसकी वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि प्रेगनेसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं।

वायरलेस डिवाइस कैसे करता है प्रभावित

दरअसल जब हम मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह के वाइफाई या वायरलेस डिवाइस के संपर्क में आते हैं तो इससे हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंडियो वेव्स निकलते रहते हैं। ये वेव्स हमारे शरीर के डीएनए को डैमज करने की क्षमता रखते हैं और हमारे शरीर में बन रहे जीवित सेल्स के मोलक्यूल्स को बदल सकते हैं। जिसका असर लॉग टर्म काफी खतरनाक हो सकता है। चूंकि भ्रूण हर वक्त ग्रोथ कर रहा है ऐसे में उसके डीएनए और लीविंग सेल्स आसानी से इसकी चपेट में आ सकते हैं। जिसका दूरगामी असर भी काफी खतरनाक हो सकता है।

क्या कहता है शोध

अलग अलग शोधों में पाया गया कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन अगर मां और बच्चा 24 घंटे मोबाइल रीडिएशन के बीच हैं तो बच्चे की मेमोरी, ब्रेन ग्रोथ और बिहेवियर में खतरनाक रूप से समस्या आ सकती है। शोधों में यह भी पाया गया कि प्री और पोस्ट डिलीवरी के बाद ऐसे बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। यही नहीं, बच्चे की भाषा, संचार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है।

इस तरह करें बचाव

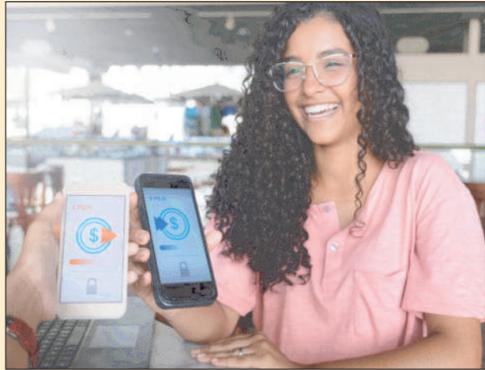
- घर में जहां तक हो सके वाई फाई या ब्लूटूथ उपकरणों का इस्तेमाल कम करें।
- बेहतर होगा अगर आप मोबाइल की बजाय लैंड लाइन फोन का इस्तेमाल करें।
- रेंडियो, माइक्रोवेव, एक्सरे मशीन आदि से दूरी बनाएं।
- मोबाइल टावर आदि के आसपास घर नालें।

गर्भावस्था में मोबाइल के नुकसान

- गर्भवती महिलाओं में रीडिएशन से मस्तिष्क की गतिविधि पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिससे थकान, चिंता और नींद में रुकावट पैदा होती है।
- गर्भावस्था के दौरान रेंडियो वेव्स के लगातार संपर्क से आगे जाकर कैंसर का खतरा बन सकता है।
- मां गर्भावस्था के दौरान फोन का अधिक इस्तेमाल करे या काफी करीबी लोग घर पर इसका इस्तेमाल करें तो बच्चे के व्यवहार में 50 प्रतिशत बदलाव देखने को मिलता है।

5 डेली लाइफ की चीजें महिलाएं जरूर सीख लें, मदद की नहीं पड़ेगी जरूरत, कदम से कदम मिलाकर चलें जमाने के साथ

जीवन में कुछ बुनियादी कौशल हैं, जिन्हें हर महिला को सीखना ही चाहिए। इन्हीं कौशलों में से एकाध हैं बच्चों की परवरिश, खाना बनाना आदि। लेकिन, आपको यह जानना जरूरी है कि इन चीजों के अलावा भी कई चीजें हैं, जिसे जल्द से जल्द सीखना महिलाओं के लिए जरूरी होता है। इन चीजों को अगर आप सीख लें तो लोगों पर निर्भरता आपकी कम होगी और आप लोगों से मदद मांगने की बजाय, उनकी मदद कर सकेंगी। जानते हैं कि बेहतर जीवन के लिए हर महिला को डेली लाइफ में किन प्रैक्टिकल स्किल को सीखना जरूरी है।



1/5 बेसिक स्किल के रूप में हर महिला को डाइविंग के अलावा टायर और इंजन ऑयल बदलना भी सीखना जरूरी है। जितना जरूरी महिलाओं के लिए डाइविंग सीखना होता है, अपनी गाड़ी से जुड़ी हर बात की जानकारी रखना भी लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। मान लें कि आप कभी आप किसी ट्रेवल में हों और आपका टायर पंचर हो जाए और आपका मोबाइल काम न करे। ऐसे में आप खुद ही गाड़ी का टायर बदल सकती हैं। वरना मदद के चक्कर में आप बुरे लोगों की चंगुल में आ सकती हैं।

Image : Canva
बेसिक स्किल के रूप में हर महिला को डाइविंग के अलावा टायर और इंजन ऑयल बदलना भी सीखना जरूरी है। जितना जरूरी महिलाओं के लिए डाइविंग सीखना होता है, अपनी गाड़ी से जुड़ी हर बात की जानकारी रखना भी लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। मान लें कि आप कभी आप किसी ट्रेवल में हों और आपका टायर पंचर हो जाए और आपका मोबाइल काम न करे। ऐसे में आप खुद ही गाड़ी का टायर बदल सकती हैं। वरना मदद के चक्कर में आप बुरे लोगों की चंगुल में आ सकती हैं।

2/5 विनम्र तरीके से और दृढ़तापूर्वक किसी को ना कहना सीखना

हर महिला को आना चाहिए। अगर आप किसी को ना नहीं कह पाती हैं तो आपको जल्द से जल्द यह सीखने की जरूरत है। इस तरह आप अपने साथ होने वाली कई अनहोनी घटनाओं को होने से रोक सकेंगी। अगर कोई आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है जिसे आप नहीं करना चाहती हैं तो आपको खुद के लिए खड़े होना सीखना होगा और 'ना' कहना होगा। विनम्र तरीके से और दृढ़तापूर्वक किसी को ना कहना सीखना हर महिला को आना चाहिए। अगर आप किसी को ना नहीं कह पाती हैं तो आपको जल्द से जल्द यह सीखने की जरूरत है। इस तरह आप अपने साथ होने वाली कई अनहोनी घटनाओं को होने से रोक सकेंगी। अगर कोई आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है जिसे आप नहीं करना चाहती हैं तो आपको खुद के लिए खड़े होना सीखना होगा और 'ना' कहना होगा।

3/5 अगर आप बजट बनाना और अपने पैसों का सही निवेश करना सीख जाती हैं, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करेंगी। अगर आप यह सीख जाएं कि कैसे अपने पैसों को इनवेस्ट करना है, तो आप जो कुछ भी जीवित नहीं करनी चाहती हैं, उसके लिए खुद पैसा पैदा भी कर सकती हैं।

खुद पैसा पैदा भी कर सकती हैं। अगर आप बजट बनाना और अपने पैसों का सही निवेश करना सीख जाती हैं, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करेंगी। अगर आप यह सीख जाएं कि कैसे अपने पैसों को इनवेस्ट करना है, तो आप जो कुछ भी जीवित नहीं करनी चाहती हैं, उसके लिए खुद पैसा पैदा भी कर सकती हैं।

4/5 अगर आप कुकिंग नहीं जानती तो आपको कदम कदम पर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। यही नहीं, आप चाहकर भी किसी को अपने हाथ से बना कुछ स्पेशल नहीं खिला पाएंगी। ऐसे में कम से कम 3 कंप्लीट डिश आप जरूर बनाना सीखें। यही नहीं, यह भी प्रयास करें कि आप रोज खाने वाले आसान डिश को भी बनाना सीख जाएं। इससे आपको हर बार बाहर के खाने को ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप हेल्दी रहेंगी।

अगर आप कुकिंग नहीं जानती तो आपको कदम कदम पर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। यही नहीं, आप चाहकर भी किसी को अपने हाथ से बना कुछ स्पेशल नहीं खिला पाएंगी। ऐसे में कम से कम 3 कंप्लीट डिश आप जरूर बनाना सीखें। यही नहीं, यह भी प्रयास करें कि आप रोज खाने

वाले आसान डिश को भी बनाना सीख जाएं। इससे आपको हर बार बाहर के खाने को ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप हेल्दी रहेंगी।

5/5 हर महिला को यह पता होना चाहिए कि आंधी के बीच, अंधेरे में किसी अपरिचित जगह पर कैसे ड्राइव करना या रास्ता ढूंढना है। अगर आप कभी खो जाएं तो अपना रास्ता कैसे खोजें। अगर आपका जीपीएस टूट जाए और रास्ता बताने के लिए कोई ना हो तो किस तरह मैप की मदद से जगह को ढूंढें। अगर आप इस तरह के कौशल को अपने अंदर पैदा कर लें तो यकीन मानिए, आप अधिक फ्री महसूस करेंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हर महिला को यह पता होना चाहिए कि आंधी के बीच, अंधेरे में किसी अपरिचित जगह पर कैसे ड्राइव करना या रास्ता ढूंढना है। अगर आप कभी खो जाएं तो अपना रास्ता कैसे खोजें। अगर आपका जीपीएस टूट जाए और रास्ता बताने के लिए कोई ना हो तो किस तरह मैप की मदद से जगह को ढूंढें। अगर आप इस तरह के कौशल को अपने अंदर पैदा कर लें तो यकीन मानिए, आप अधिक फ्री महसूस करेंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

वर्किंग वुमन के लिए बेस्ट हैं ये हेल्थ केयर टिप्स, 5 आसान तरीके करें फॉलो, हमेशा रहेंगी फिट और हेल्दी



रोजमर्रा की बिजी लाइफस्टाइल में ज्यादातर महिलाओं को अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। खासकर वर्किंग वुमन के लिए घर और ऑफिस को संभालना काफी मुश्किल टास्क होता है। हालांकि वर्किंग वुमन अगर चाहें तो कुछ आसान तरीकों की मदद से ना सिर्फ घर और बाहर की जिम्मेदारियों के बीच में अपना खास खयाल रख सकती हैं बल्कि खुद को फिट और हेल्दी भी बना सकती हैं।

घर और ऑफिस का काम करते समय महिलाएं अक्सर अपनी सेहत को नजर अंदाज कर देती हैं। जिसके चलते आप कई हेल्थ प्रॉब्लम का भी शिकार हो सकती हैं। इसलिए हम आपसे शेर्य कर रहे हैं वर्किंग वुमन के लिए कुछ आसान हेल्थ केयर टिप्स, जिसे फॉलो करके आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फुल एनजॉय कर सकती हैं।

हैवी नाश्ता करें

काम में बिजी होने के कारण कई बार वर्किंग वुमन को खाने का समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप सुबह हैवी नाश्ता कर सकती हैं। इससे ना सिर्फ आपका पेट भरा रहेगा बल्कि काम के दौरान आपको भूख का भी कम अहसास होगा और आप काम पर पूरा फोकस कर पाएंगी।

हेल्दी डाइट लें

वर्किंग वुमन अक्सर भूख लगने पर जंक फूड या तला-भुना खाकर पेट भर लेती हैं। जिससे आपके शरीर में पोषण की कमी होने लगती है और आप बीमार भी पड़ सकती हैं। इसलिए हमेशा घर का खाना खाने पर जोर दें। साथ ही डाइट में दही, सांजल फ्रूट्स और हरी सब्जियां जैसे न्यूट्रिएंट्स रिच चीजों का सेवन करें। जिससे आप फिट और हेल्दी रह सकेंगी।

भरपूर पानी पिएं

वर्किंग वुमन अक्सर काम में उलझकर समय पर पानी पीना भी भूल जाती हैं। जिससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती हैं। इसलिए काम के दौरान बीच-बीच में पानी जरूर पीएं। वहीं दिन में 8-10 गिलास पानी पीकर आप खुद को हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक रख सकती हैं।

तनाव मुक्त रहें

घर और ऑफिस का काम मैनेज करने के चक्कर में कई बार महिलाएं स्ट्रेस लेने लगती हैं। जिससे ना सिर्फ आपका मूड खराब हो जाता है बल्कि काम में भी पूरी तरह से मन नहीं लग पाता है। इसलिए काम के बीच में खुद को खुश रखने की कोशिश करें। जिससे आप तनाव मुक्त रह सकेंगी।

अपनी लाइफ में शामिल स्पेशल लेडीज को दें ये खास गिफ्ट, पाते ही खिल उठेगा उनका खूबसूरत चेहरा

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को पूरी दुनिया में 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल यह दिवस एक खास थीम को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। वर्ष 2023 की थीम 'एम्ब्रेस इक्विटी' (Embrace Equity) रखी गई है। 8 मार्च 1975 को युनाइटेड नेशंस द्वारा 'इंटरनेशनल वुमंस डे' को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। घर-परिवार, समाज आदि में महिलाओं की भागीदारी, उपस्थिति, योगदान और उनकी ताकत को सराहने, जशन मनाने का दिन है महिला दिवस। महिला दिवस पर आप अपनी जिंदगी में मौजूद हर एक स्पेशल लेडी को खास गिफ्ट देकर ये जता सकते हैं कि आपकी लाइफ में उनका कितना महत्व है। डालें कुछ शानदार गिफ्ट्स आइटम पर एक नजर।

किताबें- कई महिलाएं किताबों की बेहद शौकीन होती हैं। उन्हें अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ने का शौक होता है। यदि आपके घर में आपकी मां, बहन, मौसी, चाची या फिर दोस्त को किताबें पढ़ने का शौक है, उन्हें सहेजना, कलेक्ट करने की हॉबी है तो फिर

बुक्स से बेहतर उनके लिए कोई दूसरा सामान नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा तोहफा है, जो वर्षों आपके साथ रहता है। आप चाहें तो फिक्शन-नॉन फिक्शन, कॉमेडी, कविता, उपन्यास, कला और साहित्य जगत से संबंधित कोई भी किताब गिफ्ट कर सकते हैं। आप उनकी फेवरेट राइटर की किताब देंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी।
हर-भरे पौधे करें गिफ्ट- आजकल गिफ्ट्स में एक-दूसरे को तरह-तरह के प्लांट्स देने का ट्रेंड भी काफी बढ़ गया है। यह एक बेहतरीन गिफ्ट आइडिया इसलिए भी है, क्योंकि इसे देखते ही सामने वाले का मूड फ्रेश हो जाएगा। घर में हरियाली होने से पॉजिटिव सोच और एनर्जी भी मिलती है। घर का वातावरण फ्रेश बना रहता है। यदि आपके घर में किसी भी लेडी को प्लांट लगाने और इंडोर पौधे रखने का शौक है तो ये गिफ्ट उन्हें जरूर दें। साथ ही आप फूलों का गुलदस्ता भी दे सकते हैं।
गिफ्ट हैंडैर दें- आजकल हैंडैर देने का भी ट्रेंड खूब है। लोग अपनी को उनके फेवरेट आइटम को एक साथ पैक कर हैंडैर



तैयार कराते हैं और स्पेशल ओकेजन पर बतौर तोहफा प्रजेंट करते हैं। आप भी हैंडैर में मेकअप आइटम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, डाई प्रूट्स, चॉकलेट्स आदि चीजें मिक्स-मैच करके डलवाएं और अपनी फेवरेट लेडी को वुमंस डे पर गिफ्ट करते हुए इस दिन की डेरो बधाई दें।

घड़ी, मोबाइल करें गिफ्ट- यदि आपकी बहन, मां या फिर दोस्त को घड़ी या मोबाइल की जरूरत है तो उन्हें ये गिफ्ट देकर उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बहन या मम्मा का मोबाइल सही से चल ना रहे हो और उन्हें नया खरीदना हो। यह नेक काम आप भी

कर सकते हैं। आप दिन तरह-तरह के स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच लॉन्च होते हैं। अपने बजट के अनुसार ये गिफ्ट खरीदने का सोच सकते हैं। इयरबड्स भी देना है बेस्ट आइडिया- आजकल इयरबड्स का इस्तेमाल भी लोग खूब करते हैं। यह फायदेमंद भी है, क्योंकि

ड्राइव करते समय कान में इसे लगाकर आप किसी से भी फोन पर आराम से बात कर सकते हैं। गाने सुन सकते हैं। गिफ्ट में टेक की चीजें पाकर कोई भी खुश हो जाएगा। साथ ही इन्हें सेलेक्ट करने में भी पसंद-नापसंद वाली समस्या नहीं आती है। हां, बजट जितना हो, उसी के अंदर आप टेक आइटम खरीद कर गिफ्ट करें।
हैंडबैग दें- महिलाओं के पास जितनी वर्यायटी के हैंडबैग हैं, उतना ही उनके लिए कम होता है। तो क्यों ना आप उनके कलेक्शन में एक और स्टाइलिश डिजाइन का हैंडबैग शामिल कर दें। शॉपिंग मॉल में डेरो ब्रांडेड बैग्स उचित दामों में उपलब्ध होते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं।
जूली, इस- महिलाओं को जूली और कपड़ों का बेहद शौक होता है। शॉपिंग के लिए जब वे घर से निकलती हैं तो कुछ ना कुछ इनमें से खरीद ही लेती हैं। आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी भी लेडी को कपड़ों या जूली की जरूरत है तो आप जरूर खरीद कर गिफ्ट करें। उनका दिन बन जाएगा।

मोहल्ला क्लीनिक के लिए डॉक्टरों की निकली वैकेंसी हर बुधवार होगा इंटरव्यू; पूरी जानकारी के लिए पढ़िये खबर

दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक में डॉक्टरों के लिए वैकेंसी निकली है। इनकी नियुक्ति वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए हो रही है। इसकी जानकारी खुद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स के जरिए दी थी। यहां उन्होंने बताया है कि इंटरव्यू हर हफ्ते के बुधवार को दोपहर 2 बजे होगा। इच्छुक लोग वेब्यू पर पहुंचकर इंटरव्यू दे सकते हैं लेकिन उन्हें अपने साथ जरूरी दस्तावेज भी लाने होंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य सेवा निदेशालय इन दिनों मोहल्ला क्लीनिक में बड़े स्तर पर डॉक्टरों की नियुक्ति की पहल की है। इसके तहत वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर डॉक्टर नियुक्त किए जा रहे हैं। इच्छुक डॉक्टर प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ) कार्यालय पहुंचकर मोहल्ला क्लीनिक से जुड़ने के लिए साक्षात्कार दे सकते हैं। दिल्ली में अभी करीब 530 मोहल्ला क्लीनिक हैं। प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शनिवार को सुबह आठ बजे से दो बजे तक छह घंटे मोहल्ला क्लीनिक का संचालन होता है।

तिहाड़ जेल में HIV के 125 जबकि सिफिलिस के 200 मरीज सामने आए, 10 हजार कैदियों की कराई गई जांच

तिहाड़ जेल के 125 कैदियों के एचआईवी पीड़ित होने की खबर है। तिहाड़ जेल के नए महानिदेशक सतीश गोलवा के चार्ज लेने के बाद पिछले दो महीनों में तिहाड़ में बंद साढ़े दस हजार कैदियों की मेडिकल जांच कराई गई थी। इनमें से 125 कैदी एचआईवी संक्रमित और 200 कैदियों में सिफिलिस की बीमारी मिली है। इस दौरान टीबी का कोई भी केस सामने नहीं आया है।

पश्चिमी दिल्ली। तिहाड़ जेल में 125 कैदी एचआईवी संक्रमित और 200 कैदियों में सिफिलिस की बीमारी मिली है। एचआईवी संक्रमित कैदी नए नहीं हैं। पहले से ये एचआईवी से ग्रस्त हैं। सूत्रों के अनुसार, तिहाड़ जेल के नए महानिदेशक सतीश गोलवा के चार्ज लेने के बाद पिछले दो महीनों में तिहाड़ में बंद साढ़े दस हजार कैदियों की मेडिकल जांच कराई गई थी। इनमें से 125 कैदी एचआईवी संक्रमित और 200 कैदी कैदियों में सिफिलिस की बीमारी मिली

है। इस दौरान टीबी का कोई भी केस सामने नहीं आया है। सभी कैदी पहले से एचआईवी पीड़ित थे। हालांकि इन कैदियों को हाल ही में एचआईवी नहीं हुआ है। यह पहले से ही संक्रमित थे। वहीं इस बारे में जेल प्रशासन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि जेल में आने से पहले कैदियों की मेडिकल जांच कराई जाती है। जब ये कैदी जेल में आएं, तभी से यह एचआईवी से ग्रस्त थे।

शुगर स्ट्रिप्स की तरह रैपिड कार्ड से हेपेटाइटिस बी की हो सकेगी तुरंत जांच

देश में करीब तीन करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं लेकिन बहुत कम लोगों में बीमारी की पहचान हो पाती है। शुगर की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रिप्स जैसी रैपिड कार्ड से हेपेटाइटिस बी एंटीजन की तुरंत जांच हो सकेगी। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के रैपिड कार्ड टेस्ट हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग में ज्यादा मददगार हो सकते हैं।

नई दिल्ली। शुगर की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रिप्स जैसी रैपिड कार्ड से हेपेटाइटिस बी एंटीजन की तुरंत जांच हो सकेगी। आईएलबीएस (यूकृत व पित विज्ञान संस्थान) ने एक ऐसे ही एचबीएसएन 2 रैपिड कार्ड टेस्ट का ट्रायल किया गया, जो हेपेटाइटिस बी की पहचान में 90 प्रतिशत असरदार पाई गई है। इस ट्रायल में शामिल डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के रैपिड कार्ड टेस्ट हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग में

ज्यादा मददगार हो सकते हैं और हेपेटाइटिस बी से संक्रमित अधिक मरीजों की पहचान कर इलाज शुरू किया जा सकता है। इससे हेपेटाइटिस को दूर करने में मदद मिलेगी। आईएलबीएस के डॉक्टरों का यह अध्ययन हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल (यूरोएशियन जर्नल हेपेटोपैथोलॉजी) में प्रकाशित हुआ है। 1120 लोगों के सैमपल पर यह ट्रायल किया गया। जिसमें से 46 हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव व 74 हेपेटाइटिस बी निगेटिव लोगों के सैमपल थे। इस ट्रायल में यह जांच बीमारी की पहचान करने में 90 प्रतिशत कारगर पाई गई। साथ ही इसके नतीजे 95.5 प्रतिशत सही पाए गए। इस ट्रायल में शामिल आईएलबीएस के क्लीनिकल वायरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ. एकता गुप्ता ने बताया कि हेपेटाइटिस बी की जांच के लिए रैपिड टेस्ट की सुविधा पहले से मौजूद है, लेकिन अब तक इस्तेमाल होने वाली जांच क्रिय 60 से 70 प्रतिशत ही असरदार हैं।

यूट्यूबर्स पर नकेल, बिल लाएगी सरकार, बनेंगे नियम

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

बढ़ते मिडिया से परेशान सरकार अब यूट्यूबर्स पर शकंजा कसने की तैयारी में है। इस तैयारी के तहत सरकार बिल लाएगी और कड़े नियम भी बनाएगी। दरअसल 2024 संस्करण में डिजिटल मीडिया समाचार प्रसारक नामक श्रेणी की शुरुआत करके उन्हें कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। ब्राडकास्टर बिल के नए मसौदे में न्यू इंफ्ल्यूएंस को ब्राडकास्टर की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें उसके लिए डिजिटल समाचार प्रसारक की श्रेणी हो सकती है। यह ब्राडकास्टर सेवानियमन बिल-2024 का दूसरा मसौदा है, जो मौजूद केबल टीवी नेटवर्क कानून-1995 की जगह लेगा। इस बिल का मसौदा राय लेने के लिए इतिहासकारों से सलाह किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग नियमित रूप से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, या ऑनलाइन कंटेंट अफेयर्स के बारे में लिखते हैं, उन्हें डिजिटल समाचार प्रसारक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बता दें कि जब विधेयक पहली बार-2023 में सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था, तो इसमें प्रसारक के लिए सभी विनियमों को एक कानून के तहत संयोजित करने का प्रावधान किया गया था। शुरु से यह चिंता का विषय रहा है कि क्या ऑनलाइन समाचार सामग्री निर्माता, जो विरासत मीडिया से जुड़े नहीं हैं, स्ट्रीमिंग



प्लेटफॉर्म (ओटीटी) प्रसारण सेवाएं पर लगाए गए दायित्वों को आकर्षित कर सकते हैं या नहीं। 2024 संस्करण में डिजिटल समाचार प्रसारक नामक नई श्रेणी की शुरुआत करके उन्हें कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि नया मसौदा "समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों" को भी परिभाषित करता है जिसमें मसौदा "श्रृंखला, दृश्य, या सामग्री, संकेत लेखन, छवियों के अलावा "पाठ" भी शामिल है। कार्यक्रम और प्रसारण की परिभाषाओं को भी क्रमशः पाठ और पाठ्य कार्यक्रम को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। संक्षेप में सभी समाचार से संबंधित ऑनलाइन सामग्री सोशल मिडिया, वेबसाइटों, न्यूजलेटर्स पॉडकास्ट पर वीडियो और कमेंट्री इस बिल के अंतर्गत आती है। बता दें कि यह बिल अभी सलाह मशविरों के लिए रखी गयी है और संसद में पेश होने से पहले इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिलनी होगी। ये प्रस्तावित प्रावधान एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो स्ट्रीमिंग सेवाओं और

डिजिटल समाचार प्रसारकों में संबंधित मध्यस्थों और सोशल मीडिया मध्यस्थ के लिए नए दायित्वों का भी परिचय देते हैं और 2023 में प्रसारित श्रेणी की शुरुआत करके इनके बदलाव में, ऑनलाइन विज्ञापन को लक्षित करने वाले प्रावधान हैं। नई परिभाषा के तहत स्ट्रीमिंग सेवाओं के संदर्भ में ओटीटी प्रसारण सेवाएं अब 'इंटर्नेट प्रसारण सेवाओं की परिभाषा का हिस्सा नहीं हैं। ओटीटी प्रसारण सेवा की परिभाषा को भी संशोधित किया गया है। जिसके तहत न केवल नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो, बल्कि सामग्री निर्माता जो नियमित रूप से सोशल मीडिया पर अपनी सामग्री अपलोड करते हैं वे भी निश्चित रूप से ओटीटी प्रसारण सेवाएं हो सकते हैं। यहां ये बता दें कि नया विधेयक सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों के लिए अलग-अलग उचित परिश्रम, दिशानिर्देश निर्धारित करने की अनुमति देता है। बहरहाल सरकार अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करे।

बारिश हो या गर्मी, लोगों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है - देवेन्द्र यादव

सुष्मा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि लगातार मानसून की बारिश के बाद जल यमुना का पानी स्वच्छ और नदी साफ सुथरी दिखनी चाहिए, दिल्ली सरकार एक बार फिर यमुना में बढ़ते प्रदूषण और फास्फेट व नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से पानी में झाग हो दिखाई देने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को नकार कर नजदीकी राज्यों के औद्योगिक कचरे को यमुना में प्रदूषण बढ़ाने का कारक बता रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार अपनी नाकामियों और अधिकारियों की निष्क्रियता को यमुना में बढ़ते प्रदूषण के लिए क्यो कारण नही मानती, जबकि पिछले 10 वर्षों में हजारों करोड़ रुपये यमुना सफाई के नाम पर प्रष्टाचार की भेट चढ़ गए हैं।

उन्होंने कहा कि यमुना में बढ़ते प्रदूषण से पानी के सफेद दिखने पर दिल्ली सरकार को चिंता नहीं प्रदूषण नियंत्रित करके अमोनिया के स्तर को कम करने के उपाय करने चाहिए।



1370 किमी लम्बी यमुना पल्ला से कॉलिदी कुंज तक 54 किमी दिल्ली में बहती है जिस पर जलापूर्ति के लिए दिल्ली की ढाई करोड़ जनसंख्या निर्भर है। उन्होंने कहा कि वजीराबाद से कॉलिदी कुंज तक 22 किमी के हिस्से में 76 प्रतिशत प्रदूषण इसी हिस्से में होता है। उन्होंने कहा कि बढ़ते जल प्रदूषण को नियंत्रित करने

में फेल केजरीवाल दिल्ली की ढाई जनसंख्या के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-5 दिनों से यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली भीषण गर्मी के बाद मानसून में भी जल संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जल संयंत्रों में 0.9 पीपीएम

पाटर्स पर मिलियनड तक अमोनिया शोषित करने की क्षमता है और वजीराबाद जलाशय में अमोनिया का स्तर 2.3 पाटर्स पर मिलियन से अधिक पहुँच गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ते अमोनिया के कारण मुकद नहर से क्षमता से कम पानी मिल है, जिससे वजीराबाद, चंद्रावल, हैदपुर और बवाना का

दिल्ली में लोगों के घरों में हो रही नीले रंग के पानी की आपूर्ति, हरकत में आप सरकार; आतिशी ने दिए जांच के आदेश

परिवहन विशेष न्यूज

राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके के कई घरों में नीले रंग की पानी की आपूर्ति हो रही है। जैसे ही इसकी शिकायत की गई। दिल्ली सरकार हरकत में आई। जल मंत्री आतिशी ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह पता लगाने को कहा है कि आखिर नीले रंग के पानी की आपूर्ति कैसे हो रही है। उन्होंने सोमवार तक रिपोर्ट देने को कहा।

नई दिल्ली। पीरागढ़ी में लोगों के घरों में नीले रंग का झागदार

पानी आपूर्ति होने की शिकायत को दिल्ली सरकार ने गंभीरता से लिया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी जांच कर सोमवार शाम तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में दूषित पेयजल की आपूर्ति न हो। मंत्री ने मुख्य सचिव को जारी निर्देश में लिखा है कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है कि पीरागढ़ी के कुछ घरों में नीले रंग का झागदार पानी की आपूर्ति हो रही है। यह बहुत गंभीर है। इस मामले में तत्काल

हस्तक्षेप करने की जरूरत है। इस मामले में तत्काल संबंधित विभागों के के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई जाए।

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई उन्होंने चिढ़ी में यह पता लगाने की जरूरत है कि आखिर कैसे घरों में इस तरह का दूषित पानी पहुंच रहा है। आस पास स्थित औद्योगिक इकाइयों की भी जांच होनी चाहिए जिससे कि पता चले की प्रदूषण रोकथाम के मानक का पालन हो रहा है या नहीं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।



संस्कारशाला : परिवार के साथ समय बिताने का महत्व



प्रियंका श्रीवास्तव

आज के व्यस्त जीवन में, जहां चारों ओर शोर, विकर्षण और कर्तव्यों का दबाव है, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इस सारे हलचल के बीच, हमारा छोटा परिवार हमारी स्थिरता, हमारी चट्टान और हमारी सुरक्षित जगह है। वे ही हैं जो हमारे जीवन में खुशी, प्रेम और अर्थ लाते हैं। इसलिए, एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें, और शोर को मिटा दें। याद रखें, आपका

परिवार आपकी प्राथमिकता है। उनके मुस्कान, गले मिलना और हंसी आपके हर दिन को उज्ज्वल बनाते हैं। उनका प्रेम और समर्थन आपको शक्ति और साहस प्रदान करता है। इस सारे हलचल के बीच, हमारा छोटा जिम्मेदारियों को आपके ध्यान को उस चीज से दूर नहीं करना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपका परिवार आपको चाहता है, और आपको उनकी जरूरत है। उन पलों में उपस्थित रहें जो महत्वपूर्ण हैं - सोने की

कहानियाँ, परिवार के साथ खाना, मजेदार चुटकुले, और आरामदायक फिल्मी रातें। हर पल, हर हंसी, और हर आँसू की कद्र करें। आपका छोटा परिवार हर दिन बढ़ रहा है और बदल रहा है, और ये पल हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। प्रेम, गले मिलना और यादों को संजोएं। परिवार की परंपराओं को बनाएं, नई परंपराएं बनाएं, और उन्हें पीढ़ियों तक संजोएं। जब बाहरी दुनिया कठिन लगती है, तो आपका परिवार आपका आश्रय है। वे आपके

सच्चे दोस्त हैं, आपके अपराध में साथी, और आपके सबसे बड़े प्रशंसक हैं। इसलिए, अपने छोटे परिवार पर ध्यान केंद्रित करें, और बाकी सब कुछ पृष्ठभूमि में धुंधला हो जाए। याद रखें, आपके परिवार के लिए आपका प्रेम और ध्यान सबसे बड़ा उपहार है। उन्हें प्राथमिकता देकर, आप एक खुशहाल, विश्वासपूर्ण और रोमांचक जीवन के लिए मजबूत नींव बना रहे हैं। अपने छोटे परिवार पर ध्यान केंद्रित करते रहें -

अमन विहार में डीलर ने युवती को छत से फेंका

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके के अमन विहार में एक डीलर ने नाबालिग लडकी को छत से नीचे फेंक दिया। इस बावत छत से नीचे फेंकने की वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। डीलर फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पेरो से प्रोपर्टी डलर है। प्रात जानकारी के मुताबिक नाबालिग लडकी और डीलर के बीच प्रोपर्टी के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों एक छत पर खड़े होकर झगडा कर रहे थे। लडकी प्रोपर्टी पर आरोपी द्वारा कब्जे को वापस लेने और मौत के बीच झूल रही है। इस वारदात को देखने वालों ने आरोपी को पुलिस में सरेडर करने को कहा तो वह गाली गलौज करने लगा। इसने धमकी भरे लहजे में कहा कि जो करना है कर लो फिर छूट कर आ जाऊंगा। वायरल वीडियो में दोनों छत पर खड़े होकर झगडते दिख



रहे हैं। इतने में उक्त आरोपी ने लडकी को पिटाई कर दी और उसे छत से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए दंभिश दे रही है। इस बावत रोहिणी डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर मारपीट की धारा 115/126/(2) 351(3)79 के तहत अमन विहार थाने में केस दर्ज कर लिया है। और जांच जारी है।

फिल्मी स्टाइल में कार के बोनट पर शख्स को बैठाकर थाने में घुसा चालक, वीडियो वायरल

परिवहन विशेष न्यूज़

गाजियाबाद में ऑल्टो कार के बोनट पर एक व्यक्ति को बैठाकर चालक शालीमार गार्डन थाने में घुसा गया। दो दिन बाद इसका वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल बाइक सवार का कार सवार से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था।

गाजियाबाद। ऑल्टो कार के बोनट पर एक व्यक्ति को बैठाकर चालक शालीमार गार्डन थाने में घुसा गया। दो दिन बाद इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद शनिवार को पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल बाइक सवार का कार सवार से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था।

इंटरनेट मीडिया पर 32 सेकेंड का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति काले रंग की ऑल्टो कार के बोनट पर बैठा है। बोनट पर बैठकर वह चिल्ला रहा है। वह चालक से कार रोकने के लिए बोल रहा है। चालक कार को लेकर शालीमार गार्डन थाने में घुसा जाता है।

कार रोकने के लिए बोनट पर बैठता है शख्स

इस वीडियो के सामने आने पर पता चला कि बृहस्पतिवार को थाने से कुछ दूरी बाइक सवार व्यक्ति ने कार चालक को रोका था। दोनों के बीच पैसे का विवाद था। बाइक सवार ने अपनी बाइक खड़ी कर दी। कार चालक वहां से जाने लगा। तभी बाइक सवार व्यक्ति कार के आगे खड़ा हो जाता है।



वह कार को रोकने के लिए बोनट पर बैठ जाता है। इस दौरान चालक कार को लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर थाने भेज दिया था। उस दिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दो दिन बाद शनिवार को वीडियो प्रसारित हुआ तो पुलिस हरकत में आई। थाना कार्यालय पर तैनात मुख्य आरक्षी मनोज कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया है।

कार चालक का पता नहीं लगा पाई पुलिस पुलिस ने गाड़ी नंबर प्लेट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है लेकिन अभी पुलिस आरोपित कार चालक की तलाश नहीं कर पाई है। वहीं बोनट पर बैठे व्यक्ति तक भी पुलिस नहीं पहुंची। बताया गया कि जिस गति से आरोपित ने गाड़ी को थाने में घुसाया था उससे बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि उस दौरान थाने के

गेट पर कोई फरियादी नहीं था। दो पक्षों में पैसे के लेन-देन का विवाद की बात सामने आई है। कार चालक ने युवक को बोनट पर बैठाकर उसकी जान को खतर में डाला है। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

- निमिष पाटील, पुलिस उपायुक्त, ट्रांस हिंडन जोन

टेलीग्राम से पार्ट टाइम जॉब ऑफर, गुप पर जोड़ा और धीरे-धीरे तगे 2.89 करोड़ रुपये; फिर सामने आया आईसीआईसीआई कर्मी का हाथ

गुरुग्राम से एक बार फिर एक बड़ी साइबर ठगी की घटना सामने आई है। यहां एक शख्स को पार्ट टाइम जॉब देने के नाम पर एक टेलीग्राम गुप से जोड़ा गया और फिर धीरे-धीरे उससे दो करोड़ 89 लाख रुपये जमा करा लिए गए। जब तक वह समझ पाता कि उसके साथ ठगी हो रही है तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

गुरुग्राम। साइबर ठगों ने पार्ट टाइम जॉब के नाम पर गुरुग्राम निवासी एक युवक से बीते दिनों दो करोड़ 89 लाख रुपये की ठगी की। इस मामले की जांच के दौरान साइबर थाना पूर्वी पुलिस ने बैंक कर्मचारी समेत तीन आरोपितों को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपित ने दूसरे के नाम पर आईसीआईसीआई बैंक में कर्मचारी से मिलकर खाता खुलवाया और साइबर ठगों को बेच दिया था। डीसीपी साइबर क्राइम सिद्धांत जैन ने बताया कि सात जून को साइबर थाना पूर्वी में एक युवक ने धोखाधड़ी की शिकायत दी थी।

11 मई को टेलीग्राम से मिला जॉब का ऑफर

उसने बताया कि 11 मई को टेलीग्राम एप पर इशकारेडू नाम की युवती ने उससे संपर्क किया और अपने को ट्वेंल एजेंसी का कर्मचारी बताकर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया। इसके बाद इस युवक को गुप से जोड़ दिया गया और प्रतिदिन कमाई के लिए पैसा जमा करने को कहा गया। कई बार में इसने दो करोड़ 89 लाख रुपये जमा कर दिए। इसके बाद इसे धोखाधड़ी का अहसास हुआ। शिकायत के बाद साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस तकनीकी की सहायता से शूकरवार को तीन आरोपितों को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान उत्तर प्रदेश के ललितपुर निवासी

जितेंद्र, राजस्थान के नागौर निवासी आशीष जैन व इंदौर निवासी उत्सव चतुर्वेदी के रूप में की गई।

आशीष ने जितेंद्र के नाम पर खुलवाया था खाता

पुलिस जांच में पता चला कि आशीष जैन दुकान चलाता है। इसके पास जितेंद्र पेंडेल लोडिंग/अनलोडिंग का काम करता है। आशीष ने जितेंद्र का बैंक खाता फर्म के नाम से आईसीआईसीआई बैंक में उत्सव की मदद से खुलवाया। उस समय उत्सव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था। इस बैंक खाते को आशीष ने अपने एक अन्य साथी को 25 हजार रुपये में बेच दिया था। इस केस में ठगी गई राशि में से 60 लाख 13 हजार रुपये पता चला कि उत्सव ने दिसंबर 2023 में आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी छोड़ दी थी।

दिसंबर से जून तक इसने इंदौर में ही एक अन्य बैंक में काम किया। पुलिस टीम आरोपितों से अन्य साथियों और वारदात के बारे में पूछताछ कर रही है। जल्द ही और भी नाम सामने आ सकते हैं।

अब तक पकड़े गए बैंक कर्मचारी

26 फरवरी: मोहित राठी, महेश और विश्वकर्मा मौर्या (कोटक महिंद्रा गुरुग्राम)
2 मार्च: मु. मोकीम, अनिकेश, रोशन (यस बैंक दिल्ली)
11 मार्च: दीपक, धमेंद्र (यस बैंक, रोहिणी, दिल्ली)
1 अप्रैल: अमित (आरबीएल, हौज खास, दिल्ली)
8 अप्रैल: जेलदार बरार (एयूएसएल फाइनेंस बैंक)
10 अप्रैल: हिमांशु गंगवार (यस बैंक, राजेंद्र प्लेस दिल्ली)
10 मई: देवेंद्रशर्मा (पीएनबी, जयपुर)
20 मई: यूसूफ मोहम्मद चांद (यस बैंक, अंधेरी, मुंबई)

लाइसेंस बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर, ड्राइविंग टेस्ट देने की बदल गई जगह; एक अगस्त से नियम लागू

नोएडा के उन लोगों के लिए जरूरी खबर है। जो स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। अब उन्हें ऑनलाइन आवेदन के बाद टेस्ट के लिए एआरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद एक अगस्त से यहां पर लाइसेंस नहीं बनेगा। अब इसके लिए सभी को दादरी के पास बिसाहड़ा सेंटर पर जाना होगा।

नोएडा। स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अब टेस्ट के लिए नोएडा एआरटीओ कार्यालय नहीं जाना होगा। एक अगस्त से टेस्ट के लिए आवेदकों को दादरी के बिसाहड़ा स्थित शिवम मार्वल मोटर ट्रेनिंग सेंटर जाना होगा।

यहां प्रतिदिन 300 टेस्ट के लिए मुख्यालय की ओर से स्लाट प्रत्येक कार्यदिवस के लिए आवंटित होंगे। हालांकि प्रत्येक माह 3187 स्थाई लाइसेंस के लिए टेस्ट होता है। एआरटीओ प्रशासन सियाचम वर्मा ने बताया कि परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद एक अगस्त से अब किसी भी आरटीओ या एआरटीओ कार्यालय में स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य नहीं होगा।

आवेदकों को आनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद



ड्राइविंग टेस्ट के लिए समय और तिथि का निर्धारण होगा। इसके बाद आवेदकों को एआरटीओ कार्यालय आकर टेस्ट देना होता था, अब एक अगस्त के बाद आवेदकों को स्थाई लाइसेंस के टेस्ट के लिए एआरटीओ कार्यालय नहीं आना होगा।

इसके लिए दादरी के पास बिसाहड़ा स्थित सेंटर पर जाना होगा। ऑनलाइन मिलने वाले आवेदनों की स्क्रीन की कार्य एआरटीओ कार्यालय में होगा। टेस्ट बिसाहड़ा में होगा। वहीं से टेस्ट में पास या फेल होने का नतीजा मिलेगा। टेस्ट में सफल आवेदकों के लाइसेंस लखनऊ से प्रिंट होने के बाद आवेदक के पते पर पहुंचेंगे।

गौतमबुद्ध नगर में दो अगस्त को रहेगा अवकाश, सभी स्कूल-कॉलेज और दफतर रहेंगे बंद

गौतमबुद्ध नगर में 2 अगस्त को स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सावन मास की शिवरात्रि जलाभिषेक के तीन अगस्त के अवकाश को निरस्त कर दिया है। इसकी जगह जिला प्रशासन दो अगस्त शुक्रवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। दो अगस्त को जिले के सभी स्कूल-कॉलेज के साथ सरकारी कार्यालय में अवकाश रहेगा।

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में 2 अगस्त को स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सावन मास की शिवरात्रि जलाभिषेक के तीन अगस्त के अवकाश को निरस्त करते हुए दो अगस्त शुक्रवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। दो अगस्त को जिले के सभी स्कूल-कॉलेज के साथ सरकारी कार्यालय में अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी ने इस संबंध में जापन जारी किया है। हालांकि इस दौरान



ट्रैफिक को लेकर निर्देश पुराना ही जारी रहेगा। कांठड यात्रा के गुजरने के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात को रोककर कांठडियों को रास्ते दिखाने का काम करेंगे। लोग हेल्पलाइन नंबर 9971009001, वाट्सएप नंबर 7065100100 व ट्विटर हैंडल @noidatraffic से संपर्क कर सकते हैं। कांठडियों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन -दिल्ली-बदरपुर बार्डर ओखला बैराज से नोएडा होकर बाया गाजियाबाद होकर बुलंदशहर, हापुड, मुरादाबाद

जाने वाले भारी, मध्यम व हल्के वाहन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रयोग करेंगे। -दिल्ली से डीएनडी फ्लाईओवर होकर नोएडा से बाया गाजियाबाद होकर बुलंदशहर, हापुड, मुरादाबाद जाने वाले भारी, मध्यम व हल्के वाहन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रयोग करेंगे। -चिल्ला रेड लाइट होकर गाजियाबाद, हापुड, मुरादाबाद जाने वाले भारी, मध्यम व हल्के वाहन

कार्यालय	जिलाधिकारी	गौतमबुद्धनगर
संकेत: 1747 / मध्य सहायक / 2024	दिनांक: 27.07.2024	
कार्यालय आभ		
अवकाश कारण है कि वर्ष 2024 के स्थानीय अवकाशों की सूची में सावन मास की शिवरात्रि (जलाभिषेक) दिनांक 03.08.2024 दिन सप्ताह का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।		
जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 27.07.2024 के द्वारा सावन मास की शिवरात्रि (जलाभिषेक) दिनांक 03.08.2024 दिन सप्ताह को निरस्त करते हुए सावन मास की शिवरात्रि (जलाभिषेक) दिनांक 02.08.2024 दिन शुक्रवार का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।		
प्रतिलिपि- 1. जिलाधिकारी महोदय को अवरोधनाम। 2. सार्वजनिक विधानसभाओं को अनुमोदनार्थ। 3. जिला मुख्यालय अधिकारी को इस आदेश के प्रेषित अन्त कार्यालय आभ को दैनिक समाचार पत्रों में प्रेषण प्रकाशित करने का कष्ट करे।		
प्रमुख अधिकारी (संकेत) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।		

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रयोग करेंगे। -एमपी-01 मार्ग पर बने एलिवेटेड से होकर गाजियाबाद, हापुड, मुरादाबाद जाने वाले भारी, मध्यम व हल्के वाहन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रयोग करेंगे। -एनआईबी, माडल टाउन,

छिजारसी, ताज हाइवे से होकर गाजियाबाद, हापुड, मुरादाबाद जाने वाले भारी, मध्यम व हल्के वाहनों को वापस कर ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे से चलेंगे। -अलीगढ़, बुलंदशहर, सिन्दौराबाद से दादरी एनएच-91 होकर गाजियाबाद, दिल्ली की ओर जाने वाले भारी, मध्यम व हल्के मालवाहक वाहन ईस्टर्न पेरीफेरल का प्रयोग करेंगे।

सत्ता के लिए समर्थन जुटाता बजट

बजट पेश होते ही महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने निशाना साधा कि यह बजट नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री बच्चाओ योजना का हिस्सा है। महाराष्ट्र के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया। राज्य के विकास के लिए न कोई योजना न कोई फंड, महाराष्ट्र की उपेक्षा क्यों की गई

मतदाताओं से सौदेबाजी करने में देश के सारे राजनीतिक दल एक जैसे हैं। सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल न सिर्फ हार का बल्कि जीत का हिसाब-किताब चुकता करने से नहीं चूकते। केंद्रीय बजट 2024 में ऐसा ही कुछ चुनावी राज्यों के साथ हुआ है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके, बजट में उन्हें तो कुछ भी हाथ लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, केंद्र सरकार ने उनको भी अंगूठा दिखा दिया। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि इस बजट में देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों में संतुलन स्थापित किया गया है। इससे देश का सामूहिक और समान विकास होगा। इस बजट का ज्यादातर हिस्सा बिहार और आंध्र प्रदेश में चला गया। इससे बिगाड़ संतुलन ने बाकी राज्यों का हिसाब बिगाड़ दिया। यह बजट गठबंधन की मजबूरी का बन कर रह गया, जिसमें बड़ा हिस्सा सिर्फ दो राज्यों तक सीमित होकर रह गया। गौरवलेभ है कि केंद्र की मौजूदा सरकार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलगुदेशम और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल युनाइटेड की बैसाखियों पर टिकी है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने विशेष राज्यों का दर्जा देने की मांग पर दबाव डाला। केंद्र ने इसकी पूर्ति बजट में अलग योजनाओं के लिए प्रावधान करके कर दी। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में बजट तो पेश कर दिया, लेकिन अनुमान के मुताबिक बिहार

और आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार का बजट गड़बड़ा दिया। बजट के बड़े हिस्से पर इन दोनों राज्यों का कब्जा हो गया है। बिहार को कुल 58 हजार करोड़ तो आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ का विशेष पैकेज का ऐलान करना पड़ा। बजट पर गठबंधन सरकार का असर साफ दिखता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बाजी मार ले गए। एनडीए सरकार ने फिलहाल दोनों राज्यों को स्पेशल स्टेटस तो नहीं दिया, लेकिन उसके बदले सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसके एवज में उन राज्यों को नजरअंदाज करना पड़ा है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जोकि बीजेपी या एनडीए के लिए काफी अहम हैं। केंद्रीय बजट में चुनाव वाले राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र या झारखंड ही नहीं, बल्कि कई और अहम क्षेत्रों के लिए घोषणा नहीं हो सकी। बिहार-आंध्र के लिए विशेष पैकेज का असर यहां भी दिखा। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया शुरू कर दिया है। उम्मीद थी कि बजट में नई ट्रेनों का ऐलान होता, लेकिन नहीं हुआ। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी राज्यों को बजट से बहुत उम्मीदें थीं। इन राज्यों के लिए बजट मिलना तो दूर, कोई उम्मीद भी नहीं जगी। लोकसभा चुनावों में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के वोट छिटकने की चिंता भी नजर नहीं आई। अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए कोई खास योजना नजर नहीं आई। उम्मीद की जा रही थी कि उपयुक्त और 3 राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए मॉदी सरकार 3.0 के पहले बजट में सरकार चुनावी राज्यों के लिए अपना खजाना खोल देगी। बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है। जनजातीय समुदाय के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत जनजातीय परिवारों को सरकारी योजनाओं के संपूर्ण कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जनजाति बाहुल्य 63 हजार गांवों को



शामिल किया जाना है और पांच करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। जनजाति बाहुल्य झारखंड को कुल आबादी में करीब 27 फीसदी भागीदारी जनजातियों की है। ऐसे में इस योजना का लाभ भी झारखंड को मिलने की उम्मीद की जा सकती है। पर ये योजनाएं पार्टी की ब्रैंडिंग नहीं कर पाती हैं। जनता यह मानकर चलती है कि ये सरकारी योजनाएं हैं, यह तो मिलना ही था। अगर इनकी जगह पर कोई लोन, कोई छात्रवृत्ति, कोई सहायता जैसी योजना शुरू की गई होती तो उसकी बात अलग होती। इसी तरह चुनावी राज्यों में कोई बड़ा ध्यान नहीं है। उम्मीद की जा रही थी कि बजट में सरकार चुनावी राज्यों के लिए अपना खजाना खोल देगी। बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है। जनजातीय समुदाय के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत जनजातीय परिवारों को सरकारी योजनाओं के संपूर्ण कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जनजाति बाहुल्य 63 हजार गांवों को

के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा का ऐलान करते हुए यह भी कहा है कि 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। सवाल यह है कि किसान को पैदावार बढ़ाने से क्या मिलेगा, जब तक फसल के विकने की व्यवस्था नहीं होगी। बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ करने के वादे किए गए हैं। कोई भी एक वादा ऐसा नहीं है जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचता दिख रहा हो। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यूरे रजिस्ट्री में दर्ज किए जाएंगे, राष्ट्रीय सहकारी नीति लाई जाएगी जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आएगी। हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए जांच-पड़ताल के लिए अनुसंधान के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों की बड़ी आबादी कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए एक लाख 52 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। वित्त मंत्री ने उत्पादन बढ़ाने का बजट वादा भी अनुकूल किस्मों

हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता बनाए रखने तो झारखंड में हेमंत सोरेन को सत्ता से बाहर करने की रणनीति में जुटा है। बीजेपी ने यहां चुनावी मुनादी कर दी, लेकिन बजट ने उसका खेल बिगाड़ दिया। विपक्ष इन राज्यों की उपेक्षा का आरोप लगाकर हमलावर है। चुनावों तक यह विरोध और भी तेज होने की संभावना जताई जा सकती है। महाराष्ट्र की तरह ही झारखंड राज्य के लिए भी अलग से इस बजट में कोई विशेष योजना या प्रावधान नहीं है, जबकि इस साल के अंत तक झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हालांकि पूर्णोदय योजना, जिसे सरकार ने 'विकास भी विरासत भी' नाम दिया है, के तहत जिन पांच राज्यों को शामिल किया है, उनमें बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ झारखंड राज्य भी है। पांच राज्यों में गौर करें तो इनमें ओडिशा में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। लिहाजा प्रदेश को सरकार ने तोहफा दिया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को गठबंधन समझौते के तहत तबज्जो देना लाजिमी था, लेकिन चीकाने

वाली बात यह है कि इनमें पश्चिम बंगाल को भी शामिल किया गया है, जहां निकट भविष्य में भी चुनाव नहीं है, बल्कि हाल के उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बजट पेश होते ही महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने निशाना साधा कि यह बजट नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बच्चाओ योजना का हिस्सा है। महाराष्ट्र के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया। राज्य के विकास के लिए न कोई योजना न कोई फंड, महाराष्ट्र की उपेक्षा क्यों की गई? महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन बजट में प्रदेश के हित से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सका। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे और सांसद राहुल गांधी ने भी कहा कि यह देश का बजट नहीं है। महाराष्ट्र के लिए न कोई फंड में सत्ता में बने रहने की मजबूरी ने बजट को असंतुलित कर दिया। दो राज्य देश के दूसरे राज्यों पर भारी पड़ गए।

- सौजन्य -

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस-वे बनाने की तैयारी, 1700 हेक्टेयर में लगेगा प्लांट

परिवहन विशेष न्यूज

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस-वे बनाने की तैयारी है। इसको लेकर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शुक्रवार 26 जुलाई को 6 कालीदास मार्ग स्थित कैप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ

बैठक की।

इसमें सोलर एक्सप्रेस-वे के निर्माण के संबंध में 9 अगस्त को लखनऊ में सभी हितधारकों व सौर ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ सेमिनार और 10 अगस्त को प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य के साथ ही प्रगति की समीक्षा बैठक व निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि बिजली भी पैदा होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर 25 हजार से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। 1700 हेक्टेयर जमीन पर प्रदेश का सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए कंपनियों को 25 साल के लिए लीज पर जमीन आवंटित की जाएगी।

इटावा से चित्रकूट तक 296

किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के मुख्य कैरिजवे और सर्विस रोड के बीच स्थित 1700 हेक्टेयर भूमि पर 15-20 मीटर की चौड़ाई में सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए कंपनियों को 25 साल के लिए लीज पर जमीन आवंटित की जाएगी।



मुरादाबाद में ई-रिक्शा संचालन के लिए पांच जोन तय, एक अगस्त से होगा लागू, मालिक का पता होगा अनिवार्य

परिवहन विशेष न्यूज

मुरादाबाद की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब जोन के हिसाब से ई-रिक्शा का संचालन किया जाएगा। इसके लिए शहर में पांच जोन तय किए गए हैं। जिस व्यक्ति के नाम पर ई-रिक्शा रजिस्टर्ड है, उसके पते के हिसाब से जोन लागू किया जाएगा।

सब कुछ ठीक रहा तो एक अगस्त से जोन के अंतर्गत शहर में ई-रिक्शा का संचालन शुरू हो जाएगा। शहर में करीब 15 हजार ई-रिक्शा पंजीकृत हैं, लेकिन सड़कों पर 20 हजार से अधिक ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं। दूसरे कस्बों और शहरों के नाम से पंजीकृत ई-रिक्शा भी यहां चल रहे हैं।

जोन व्यवस्था लागू होने के बाद बाहरी ई-रिक्शा पर रोक लग जाएगी। एसपी टैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि जोन लागू होने के बाद यदि कोई ई-रिक्शा दूसरे जोन में चलता मिला तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा दूसरे शहरों के लिए पंजीकृत ई-रिक्शा भी शहर में नहीं चल सकेंगे। परिवहन विभाग के अधिकारियों से पंजीकृत ई-रिक्शा की सूची मांगी गई है। सूची मिलने पर ई-रिक्शा के लिए जोन तय किए जाएंगे।



जोन 1: लाइन पार, मानसरोवर कॉलोनी, प्रकाश नगर, रामलीला मैदान, कुंदनपुर, विकास नगर, हनुमान नगर, चाऊ की बस्ती, एकता कॉलोनी, ढक्खा, पैतपुरा, जयंतपुर, पीर का बाजार, करुला, पुतली घर रोड, चौहान वाली मिलक।
जोन 2: बुद्धि विहार, कांशीराम नगर, मिलन विहार, खुशहालपुर, बुद्धिपार्क, शाहपुर तिगरी, सम्राट अशोक नगर, प्रीत विहार, चंद्र नगर,

आवास विकास पीली कोठी, रेलवे कॉलोनी, केंद्रीय विद्यालय, आदर्श कॉलोनी, हिमगिरी कॉलोनी, हरथला, रेलवे हरथला कॉलोनी, मोरा की मिलक।
जोन 3: पुलिह अकादमी, पुलिस लाइन, जिगर कॉलोनी, बंगलागांव, दौलत बाग, चक्कर की मिलक, पुराना आरटीओ ऑफिस, कचहरी, नवीन नगर, रामगंगा विहार, आशियाना कॉलोनी, मौरा, साई

मंदिर, वेव सिटी, टीडीआई सिटी, दीनदयाल नगर।
जोन 4: इंपीरियल तिराहा, बुध बाजार, मानपुर, कटरा नाज, अमरगो गेट, मंडी चौक, संभली गेट, हेलट रोड, बाजार गंज, टाउन हॉल, बार्टन बाजार, सराफा बाजार, पार्कर रोड, कंजरी सराय, गुहारट्टी चौराहा, जेल रोड, जैन मंदिर रोड, कंपनी बाग, बागदारी, मंडी चौक, दीवान का बाजार, लाल बाग, तहसील स्कूल,

एस कुमार, रेती स्ट्रीट, फैज गंज, पीरगंज, जोआईसी चौराहा, जामा मस्जिद चौराहा, ताजपुर माफी, किसरील, कानून गोयान, नवाबपुरा।
जोन 5: बरवाला, गुलाबवाड़ी, अटल घाट, कटघर रेलवे स्टेशन, मकबरा, लाजपत नगर टाउन, संभल चौराहा, गांधी नगर, पीरजादा, ईदगा, असालतपुरा, प्रिंस रोड, इंद्रा चौक, लंगड़े की पुलिया, भूड़े का चौराहा।

गोरखपुर की महिलाओं को मिलेगा रोजगार, चलाएंगी ई-रिक्शा



परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर में महिलाओं को रोजगार देने के लिए नगर निगम ने खास मुहिम शुरू की है। जिसके जरिए शहर की महिलाओं को भी रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम शुरूआती दौर में 50 महिलाओं को 'पिक ई-रिक्शा' देगा। जिससे वे कमाई कर सकेंगी और उन्हें हर दिन 400 से 500 रुपये नगर निगम में जमा करने होंगे। 4 साल बाद यह ई-रिक्शा पूरी तरह से उन महिलाओं का हो जाएगा जो इसकी लाभार्थी होंगी। नगर निगम का डूबा विभाग ई-रिक्शा की चार्जिंग और पार्किंग की व्यवस्था भी करेगा, ताकि महिलाएं इसे चार्ज कर सकें। यह पार्किंग और चार्जिंग सुविधा गोरखनाथ ओवर ब्रिज के पास बनाई जाएगी। पिक ई-रिक्शा के लिए सरकार ने निजी कंपनियों से अनुबंध किया है। इस मिशन के जरिए महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने पर खास करीब 700 से 1000 रुपये का नगर निगम निजी कंपनियों से

महिलाओं को 'ई-रिक्शा' उपलब्ध कराएगा। ई-रिक्शा मिलने के बाद 4 साल तक हर दिन 400 से 500 रुपये नगर निगम में जमा करने होंगे। 4 साल बाद यह ई-रिक्शा पूरी तरह से उन महिलाओं का हो जाएगा जो इसकी लाभार्थी होंगी। नगर निगम का डूबा विभाग ई-रिक्शा की चार्जिंग और पार्किंग की व्यवस्था भी करेगा, ताकि महिलाएं इसे चार्ज कर सकें। यह पार्किंग और चार्जिंग सुविधा गोरखनाथ ओवर ब्रिज के पास बनाई जाएगी। पिक ई-रिक्शा के लिए सरकार ने निजी कंपनियों से अनुबंध किया है। इस मिशन के जरिए महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने पर खास करीब 700 से 1000 रुपये का नगर निगम निजी कंपनियों से

अनुबंध करेगा। ई-रिक्शा खरीदने वाली महिलाओं को देने से पहले उन महिलाओं का चयन किया जाएगा जिन्हें वे ई-रिक्शा दिए जाने हैं। फिर उन्हें विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ही महिलाओं को ई-रिक्शा दिए जाएंगे। अपर नगरावृत्त मणि भूषण तिवारी का कहना है कि आजीविका मिशन के तहत यह काम किया जा रहा है। पहले 4 साल तक महिलाओं को ई-रिक्शा का तय किराया कंपनी को जमा करना होगा। इसके बाद बचा हुआ मुनाफा वे रख सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इससे महिलाओं को हर दिन करीब 700 से 1000 रुपये का फायदा होगा।

बरेली में ई-रिक्शा आनकॉल सर्विस की तैयारी



परिवहन विशेष न्यूज

एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। हितेश कुमार का स्टार्टअप भी इसी आइडिया का हिस्सा है। उन्होंने मुरादाबाद में ओला उबर की तरह ई-रिक्शा ऑन कॉल सर्विस शुरू करने का आइडिया आया। उन्होंने फ्यूज इट ऐप बनाया और शुरूआत में कुछ इलाकों में सक्नी और फल विक्रेताओं को जोड़कर यह सेवा शुरू की, उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अब वे इसे पूरे शहर में शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। कॉलोनियों में इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले सक्नी और फल विक्रेता भी ई-रिक्शा में घूमते हैं।

कॉलोनी के लोग इनसे सामान खरीदते हैं। अब प्रेम नगर और वीर सावरकर नगर में भी यह सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। शहर के स्थानीय उत्पादों और बाजारों का लोग भी इस ऐप का लाभ उठा सकेंगे। हितेश के मुताबिक यह प्रोजेक्ट जनता को विक्रेताओं से जोड़ेगा। अगर किसी के घर में शादी है तो वह इस ऐप के जरिए पता लगा सकेगा कि शहर की कौन सी दुकान शादी के सामान की खरीद पर ऑफर या छूट दे रही है। दुकानदार अपने उत्पादों और ऑफर की जानकारी इस ऐप पर डालेंगे और जनता उसे देखकर खरीदारी कर सकेगी।

दिया।

हितेश अब इस प्रोजेक्ट को पूरे शहर में शुरू करने जा रहे हैं। इससे सैकड़ों ई-रिक्शा चालकों को रोजगार मिलेगा। लोग रात में भी सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। महानगर, मेगा सिटी, ट्यूबलैप ग्रैंड अपार्टमेंट के लोग ऐप के जरिए फल और सब्जियां खरीद रहे हैं। वे ऐप के जरिए सामान बुक करते हैं और तय समय में सामान उनके घर पहुंच जाता है। कॉलोनियों में इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले सक्नी और फल विक्रेता भी ई-रिक्शा में घूमते हैं।

कॉलोनी के लोग इनसे सामान खरीदते हैं। अब प्रेम नगर और वीर सावरकर नगर में भी यह सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। शहर के स्थानीय उत्पादों और बाजारों का लोग भी इस ऐप का लाभ उठा सकेंगे। हितेश के मुताबिक यह प्रोजेक्ट जनता को विक्रेताओं से जोड़ेगा। अगर किसी के घर में शादी है तो वह इस ऐप के जरिए पता लगा सकेगा कि शहर की कौन सी दुकान शादी के सामान की खरीद पर ऑफर या छूट दे रही है। दुकानदार अपने उत्पादों और ऑफर की जानकारी इस ऐप पर डालेंगे और जनता उसे देखकर खरीदारी कर सकेगी।

जयपुर शहर में रोजाना कितने ई-रिक्शा चलते हैं, जानकर हैरान रह जाएंगे

परिवहन विशेष न्यूज

जयपुर की सड़कों पर 40 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं। इनकी वजह से शहर की यातायात व्यवस्था अक्सर जाम हो जाती है। सरकार के प्रयास असफल साबित हो रहे हैं। 26 जुलाई शुक्रवार को सरकार ने विधानसभा में माना है कि जयपुर शहर में कुल 41762 ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं। ये वो आंकड़े हैं, जो सरकार के पास हैं। इसके अलावा कई ई-रिक्शा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या पचास हजार को पार कर सकती है। वर्तमान में वाहनों के रजिस्ट्रेशन का कार्य परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। जिसमें रजिस्ट्रेशन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अनुसार वाहन मालिक का पता निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में जयपुर-I अधिकार क्षेत्र में कुल 39878 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं तथा जयपुर-II अधिकार क्षेत्र में 1884 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं। इनमें परकोटा क्षेत्र के ई-रिक्शा भी शामिल हैं। ट्रेफिक जाम और ई-रिक्शा की बेरतरीब ड्राइविंग को रोकने के लिए ट्रेफिक पुलिस भी अलर्ट पर है। इस



साल जनवरी से 15 जुलाई तक 29,218 ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से 930 के खिलाफ चालान जारी किए गए हैं। इसके अलावा 3064 ई-रिक्शा जब्त किए गए हैं। ई-रिक्शा की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार के प्रयास किये जा रहे हैं। 01. ई-रिक्शा का स्वामित्व लाइसेंस धारक के नाम पर होना

चाहिए अर्थात् ई-रिक्शा का संचालन उसके पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा ही किया जाएगा। 02. एक व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक ई-रिक्शा पंजीकृत नहीं होंगे। 03. राज्य सरकार स्थानीय यातायात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट क्षेत्र या मार्ग में ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगाएंगी। 04. जयपुर विकास प्राधिकरण के यातायात नियंत्रण बोर्ड की 19 जुलाई को हुई बैठक में जयपुर शहर में ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित करने के लिए 6 जोन बनाने तथा जोनवार ई-रिक्शा की अधिकतम संख्या निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन जयपुर द्वारा यह कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है।

टाटा कर्व ईवी को मिलेंगे कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स, 7 अगस्त को रही है मेगा एंट्री

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा सफारी की तरह आने वाली टाटा कर्व में इलेक्ट्रिक टेलगेट होगा जिसे हाइडर ट्रिप्स में पेश किया जाएगा। टाटा कर्व ईवी इस फीचर्स के साथ आने वाली सेगमेंट की पहली कूप एसयूवी होगी इन सभी सेगमेंट-फर्स्ट पेशकशों के अलावा कर्व कूप एसयूवी में वॉयस असिस्टेंस के साथ पैनोरमिक सनरूफ लेवल 2 ADAS तकनीक टाटा की iRA कनेक्टेड तकनीक और एम्बिएंट लाइटिंग होगी।

नई दिल्ली। Tata Curvv EV भारतीय बाजार में 7 अगस्त, 2024 को एंट्री मारेगी। इसे शुरूआत में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध कराया जाएगा, इसके बाद सितंबर के शुरूआती हफ्तों में इसका ICE वर्जन भी पेश होगा।

Citroen Basalt से होगी सीधी टक्कर

Tata Curvv EV का सीधा मुकाबला आगामी Citroen Basalt से होने वाला है। भारतीय ऑटोमेकर टाटा मोटर्स ने इसे कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स देने वाली है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला बड़ा 12.3 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 8-स्पीकर वाला हरमन साउंड सिस्टम शामिल है। यह यूनिट हुंडई क्रेटा के 10.25 इंच के इन्फो यूनिट से बड़ी है। इसके अलावा, कूप एसयूवी में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, जिसमें डेडिकेटेड मैप व्यू होगा और इसे नेक्स्टन ईवी से लिया गया है।

मिलेंगे ये सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स

टाटा सफारी की तरह, आने वाली टाटा कर्व में इलेक्ट्रिक टेलगेट होगा, जिसे हाइडर ट्रिप्स में पेश किया जाएगा। टाटा कर्व ईवी इस



फीचर्स के साथ आने वाली सेगमेंट की पहली कूप एसयूवी होगी। इस कूप एसयूवी के हाइडर ट्रिप्स में फ्लश-फिटेड डोर हैंडल होने की उम्मीद है, जैसा कि Mahindra XUV700 में देखा गया है। इन सभी सेगमेंट-फर्स्ट पेशकशों के

अलावा, कर्व कूप एसयूवी में वॉयस असिस्टेंस के साथ पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS तकनीक, टाटा की iRA कनेक्टेड तकनीक, एम्बिएंट लाइटिंग, थ्री-स्टेप मेमोरी फंक्शन के साथ 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, फ्रंट और रियर

टाइप सी चार्जर, लेदेर अपहोल्स्ट्री, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑन-डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और बहुत कुछ दिया जाएगा। टाटा की नई कूप एसयूवी में 500 लीटर का बूट स्पेस होगा।

महिंद्रा के साथ ओला भी करेगी 15 अगस्त को बड़ा एलान! तैयार हो रही इलेक्ट्रिक बाइक

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में अभी तक किसी भी प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता ने प्रवेश नहीं किया है और ओला अपनी शुरूआत में पहले स्थान पर रहने की कोशिश करेगी। ओला ने अभी तक बेहतर प्रोडक्ट पेश किए हैं तो ऐसे में उम्मीद है कि अपकॉमिंग बाइवस भी बेहतर होगी। जारी की गई इमेज में आप सीट का हिस्सा BMS (बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम) और फुटपेग भी देख सकते हैं।

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक वर्तमान में देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी है। इंडियन मार्केट में इसकी Ola S1 रेंज को खूब पसंद किया गया है। ब्रांड अब जीरो एमीशन वाले नए 2-Wheelers प्रोडक्ट्स पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी जल्द ही इलेक्ट्रिक बाइक स्पेस में प्रवेश करने वाली है।

ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले साल 15 अगस्त 2023 को Diamondhead, Roadster, Adventure और Cruiser नाम से 4 कॉन्सेप्ट पेश किए थे। हाल ही में ओला ने नई मोटरसाइकिल डिजाइन का पेटेंट कराया है जो

आगामी उत्पादन मॉडल की ओर इशारा करती है। इसके तुरंत बाद, बेंगलुरु स्थित ब्रांड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाविश अग्रवाल ने एक स्टील ट्यूबलर फ्रेम के भीतर एक बड़े बैटरी पैक की एक तस्वीर पोस्ट की और हम इसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए भी इस्तेमाल किए जाने के और संकेत देख सकते हैं।

टीजर इमेज में क्या दिखा ?

बैटरी पैक के आकार से पता चलता है कि यह एक ई-मोटरसाइकिल के लिए तैयार की गई है और चैन ड्राइव और स्प्रॉकेट का एक हिस्सा इस बात का संकेत देता है कि ओला हाल ही में लॉन्च की गई UV F77 Mach 2 जैसा ही सेटअप अपना सकती है। जारी की गई इमेज में आप सीट का हिस्सा, BMS (बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम) और फुटपेग भी देख सकते हैं। महिंद्रा की तरह ही ओला भी 15 अगस्त को बड़ी घोषणाएं या खुलासे करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू होने वाला है। बैटरी पैक का वजन और चैसिस के भीतर इसकी स्थिति आगामी मॉडल की हैडलिंग विशेषताओं और वजन वितरण को स्पष्ट रूप से निर्धारित करेगी।

1.4 लाख के तक पहुंची स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की संख्या, यूपी से आगे निकला गुजरात

परिवहन विशेष न्यूज

देश में स्टार्टअप की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिली है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 1.4 लाख पहुंच गई है। राज्यों के हिसाब से सबसे आगे महाराष्ट्र है। भारत सरकार स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए कई कदम उठा रही है। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में स्टार्टअप की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि भारत में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की संख्या 1.4 लाख के पार पहुंच गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी रजिस्टर्ड स्टार्टअप डेटा की लिस्ट के अनुसार महाराष्ट्र टॉप पर है।

किस राज्य में कितनी है स्टार्टअप की संख्या

भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप की संख्या महाराष्ट्र में है। यहां 25,044 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं।

इस लिस्ट में कर्नाटक दूसरे नंबर पर आता है। यहां 15,019 पंजीकृत स्टार्टअप हैं। कर्नाटक के बाद दिल्ली का नाम है। दिल्ली में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या



14,734 हैं।

उत्तर-प्रदेश चौथे पायदान पर है। यूपी में स्टार्टअप की संख्या 13,299 है।

वहीं, गुजरात ने पांचवें स्थान पर है।

गुजरात में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 11,436 है।

सरकार कर रही है स्टार्टअप को प्रमोट

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री

जितिन प्रसाद ने बताया कि सरकार स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए कई कदम उठा रही है।

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी। यह पहल देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।

इसके अलावा 'स्टार्टअप इंडिया एक्शन

प्लान' में रिसिलिफिकेशन और हैंडहोल्डिंग, रूफिंग समर्थन और प्रोत्साहन, ₹ और उद्योग-अकादमिक साझेदारी और इन्क्यूबेशन जैसे क्षेत्रों में फैले

19 एक्शन आइटम शामिल हैं। 'स्टार्टअप इंडिया: द वे अहेड' में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर

भारत ने भी अहम भूमिका निभाई है। सरकार

ने स्टार्टअप की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष

के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) की भी स्थापना की है। सरकार ने न केवल शुरूआती चरण, सीड स्टेज और ग्रोथ स्टेज में स्टार्टअप के लिए पूंजी

खुशखबरी! NCCF बेचेगी 60 रुपये प्रति किलो में टमाटर, दिल्ली और नोएडा की मार्केट में लगे स्टॉल



NCCF ने टमाटर के रिटेल सेल को 60 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की है। कृषि भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी कॉलोनी हाउस खास हेड ऑफिस संसद मार्ग आईएनए मार्केट मंडी हाउस आईएनए मार्केट मंडी हाउस कैलाश कॉलोनी आईटीओ साउथ एक्सटेंशन मोती नगर द्वारका नोएडा सेक्टर 14 और सेक्टर 76 रोहिणी और गुरुग्राम सहित कई स्थानों पर टमाटर की खुदरा बिक्री 60 रुपये प्रति किलो होगी।

नई दिल्ली। टमाटर के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को राहत देने के लिए NCCF ने Tomato Price Cut की घोषणा की है। एनसीसीएफ ने टमाटर के रिटेल सेल को 60 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 29 जुलाई से दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर होगी।

इन जगहों पर लगे स्टॉल

कहा गया है कि कृषि भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉलोनी, होज खास हेड ऑफिस, संसद मार्ग, आईएनए मार्केट, मंडी हाउस, कैलाश कॉलोनी, आईटीओ, साउथ एक्सटेंशन, मोती नगर, द्वारका, नोएडा सेक्टर 14 और सेक्टर 76, रोहिणी और गुरुग्राम सहित कई स्थानों पर टमाटर की खुदरा बिक्री 60 रुपये प्रति किलो होगी।

मार्केट की मौजूदा स्थिति

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में टमाटर की कीमतें फिलहाल 100 से 120 रुपये प्रति किलो के बीच हैं। हालांकि, अगले महीने कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। मंडी के कुछ थोक व्यापारियों का अनुमान है कि जब तक स्थानीय खेतों से टमाटर आना शुरू नहीं होगा, तब तक कीमतों में तेजी जारी रहेगी। पिछले साल भी टमाटर की कीमतें 150 से 180 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थीं, लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते में इसमें गिरावट आई थी।

33 हजार करोड़ के पार पहुंचा जुलाई में एफपीआई निवेश, विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजारों में खूब दिलचस्पी



परिवहन विशेष न्यूज

बीते सप्ताह एफपीआई ने कुल पांच में से दो सत्रों में खरीदारी और तीन में बिक्री की। सप्ताह के दौरान एफपीआई ने शुद्ध रूप से 2918.16 करोड़ रुपये का निवेश किया। डेट या बॉन्ड बाजारों की बात करें तो 26 जुलाई तक एफपीआई 19223 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। इसके साथ वर्ष 2024 में डेट बाजारों में एफपीआई का कुल निवेश 87848 करोड़ रुपये हो गया है।

नई दिल्ली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का भारतीय बाजारों में आकर्षण बना हुआ है। यही कारण है कि घरेलू इक्विटी बाजारों में 26 जुलाई तक एफपीआई का

शुद्ध निवेश बढ़कर 33,688 करोड़ रुपये हो गया है। नेशनल सिन्क्रोटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डाटा के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक इक्विटी बाजारों में एफपीआई का शुद्ध निवेश 36,888 करोड़ रुपये हो गया है।

बीते सप्ताह एफपीआई ने कुल पांच में से दो सत्रों में खरीदारी और तीन में बिक्री की। सप्ताह के दौरान एफपीआई ने शुद्ध रूप से 2,918.16 करोड़ रुपये का निवेश किया। डेट या बॉन्ड बाजारों की बात करें तो 26 जुलाई तक एफपीआई 19,223 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। इसके साथ वर्ष 2024 में डेट बाजारों में एफपीआई का कुल निवेश 87,848 करोड़ रुपये हो गया है। 2024 में अब तक इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और अन्य इंस्ट्रूमेंट में

एफपीआई का निवेश 1.39 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि ज्यादा मूल्यांकन और पहली तिमाही के परिणाम उम्मीद से कम रहने के चलते विदेशी निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं। हालांकि, घरेलू निवेशक कम मूल्य पर खरीदारी की रणनीति अपना रहे हैं। इससे बीते सप्ताह के अंतिम सत्र में बाजारों को बढ़त हासिल करने में मदद मिली है।

बीते सप्ताह निवेश की स्थिति

22 जुलाई 1,824.07
23 जुलाई 8,346.73
24 जुलाई -1,548.64
25 जुलाई -3,508.22
26 जुलाई -2,197.78

35 प्रतिशत बढ़ी सोने के आभूषणों की खरीदारी, सीमा शुल्क कम होने से सराफा बाजारों में लौट रही रौनक

भविष्य की शादियों के लिए अभी खरीदारी हो रही है। वित्त मंत्री ने सोने-चांदी के आयात पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया है। इससे सोने-चांदी के मूल्य में भी कमी आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के सचिव सुरेन्द्र मेहता का कहना है कि सीमा शुल्क घटाने का फैसला सोने का गैरकानूनी कारोबार करने वालों के अलावा सभी के लिए अच्छा रहा है।

नई दिल्ली। आम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से सोने पर बैसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) घटाने की घोषणा का बाजार में असर दिख रहा है। वित्त मंत्री की घोषणा के अगले ही दिन सराफा बाजारों में रौनक लौट आई है। निवेशकों के साथ शादी-ब्याह के लिए भी आभूषणों की खरीदारी शुरू हो गई है। बाजार से जुड़े लोग बताते हैं कि विगत चार दिनों में सोने व चांदी के गहनों की खरीद करीब 35 प्रतिशत बढ़ गई है।

शादियों के लिए सोना खरीद रहे लोग
भविष्य की शादियों के लिए अभी खरीदारी हो रही है। वित्त मंत्री ने सोने-चांदी के आयात पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया है। इससे सोने-चांदी के मूल्य में भी कमी आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के सचिव सुरेन्द्र मेहता का कहना है कि सीमा शुल्क घटाने का फैसला सोने का गैरकानूनी कारोबार करने वालों के अलावा सभी के लिए अच्छा रहा है। सोने की महंगाई की वजह से सराफा बाजारों में ग्राहकों की संख्या घट गई थी। अब लोग फिर से बाजार में लौटेंगे। निवेश के लिए लिहाज से भी लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है।

वित्त मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं सीमा शुल्क में कमी लाने का वास्तविक उद्देश्य तस्करी में कमी लाना था। खासतौर पर दुबई के



भविष्य की शादियों के लिए अभी खरीदारी हो रही है। वित्त मंत्री ने सोने-चांदी के आयात पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया है। इससे सोने-चांदी के मूल्य में भी कमी आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के सचिव सुरेन्द्र मेहता का कहना है कि सीमा शुल्क घटाने का फैसला सोने का गैरकानूनी कारोबार करने वालों के अलावा सभी के लिए अच्छा रहा है।

रास्ते आने वाले सस्ते सोने का आयात खत्म होगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कारोबार समझौता होने के कारण अभी तक वहां सोना-चांदी के आयात पर आठ प्रतिशत शुल्क लगाता था। अब कहीं से भी सोना आयात करने पर छह प्रतिशत शुल्क लागेगा। मेहता इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट

(कमोडिटीज) के राहुल कालात्री का कहना है कि भारत में सोने का मूल्य तीन सप्ताह और चांदी का मूल्य 11 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर है।

यह सिर्फ आम बजट के नए प्रावधान का ही नहीं, बल्कि अमेरिकी बाजार का भी असर है। अमेरिका में फेडरल बैंक की तरफ से संकेत है

कि वह निकट भविष्य में रेट कम नहीं करेगा। इसके अलावा, चीन के केंद्रीय बैंक की तरफ से दरों में कटौती के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने व चांदी की भारी बिक्री हुई है। इसका कारण यह है कि चीन का केंद्रीय बैंक बाहर से सोने की खरीद कर रहा है।

ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल ने कहा 'जिन लोगों के घरों में आगामी दिनों में शादियां हैं, वह लोग तो आ ही रहे हैं। साथ ही सोने में निवेश करने वाले ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है। सामान्य दिनों के मुकाबले ग्राहकों की संख्या करीब 30 प्रतिशत बढ़ी है। सीमा शुल्क में कमी से बाजा को ऊर्जा मिली है। बजट के बाद से अब तक 10 ग्राम सोने के मूल्य में करीब पांच हजार रुपये की कमी आई है।

3 घंटे लेट हुई ट्रेन, तो मिल सकता है रिफंड, प्रोसेस के साथ जानें क्या हैं शर्तें

देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इसका असर भारतीय रेलवे के संचालन पर पड़ रहा है। कई जगह ट्रेन देरी से चल रही है या फिर कैंसिल हो रही है। ऐसे में यात्री बड़ी आसानी से रिफंड के क्लेम कर सकते हैं। जी हां अगर 3 घंटे या उससे ज्यादा की देरी से ट्रेन चलती है तो यात्री पूरे रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं।

नई दिल्ली। भारी बारिश की वजह से ट्रेन संचालन में देरी हो रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें मुंबई के रेलवे ट्रेक पर मछली तैरते हुए दिखाई। ट्रेन की देरी से चलने पर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे में यात्रियों के पास अधिकार होता है कि अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा की देरी से चलती है तो वह टिकट रिफंड ले सकते हैं। आज हम आपको भारतीय रेलवे (Indian Railway) के ट्रेन टिकट रिफंड से जुड़े नियमों के बारे में बताएंगे।

भारतीय रेलवे के नियम व शर्तें
आप जिस ट्रेन से सफर करने वाले हैं, लेकिन वह ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही है तो आप आसानी से रिफंड के क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा



कर्मचारी तत्काल टिकट वाले यात्रियों को नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कंपर्म तत्काल टिकट है तो आप उसके लिए रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं।

रिफंड क्लेम करने के लिए यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रसीद फाइल करनी होती है। आप आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन यानी टिकट काउंटर पर भी जाकर रिफंड क्लेम

कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार टीडीआर फाइल करने के 90 दिन के भीतर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा आ जाएगा।

ऑनलाइन टीडीआर फाइल करने का प्रोसेस

सबसे पहले IRCTC के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।

अब 'Services' के ऑप्शन में जाकर 'File Ticket Deposit

Receipt (TDR)' पर क्लिक करें। इसके बाद My Transactions के टैब में 'File TDR' को सेलेक्ट करें।

अब आपको क्लेम रिक्वेस्ट भेजना होगा। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपको कुछ दिनों में रिफंड आ जाएगा।

आपको बता दें कि टिकट रिफंड उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से टिकट बुक हुई है। ऑफलाइन टिकट सरेंडर करने पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होंगी।

यूएई, बहरीन के अलावा दुनिया के कई देशों में जनता नहीं देती इन्कम टैक्स, चेक करें टैक्स-फ्री देशों की लिस्ट

देश के संचालन में इनकम टैक्स की अहम भूमिका होती है। कहा जाता है कि जनता द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से ही सरकार की कमाई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां लोग टैक्स नहीं देते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि इन देश की इकोनॉमी कैसे चलती है। इस आर्टिकल में टैक्स फ्री देशों की लिस्ट चेक करते हैं।

नई दिल्ली। टैक्स किसी भी देश के संचालन के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि देश की इकोनॉमी में जनता द्वारा दिए जाने वाले टैक्स की अहम भूमिका होती है। लेकिन, दुनिया के कई देश ऐसे भी जहां जनता से कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। इस लिस्ट में यूएई, सऊदी अरब जैसे कई देशों के नाम शामिल हैं। आइए, जानते हैं कि दुनिया में किन देश के नागरिकों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है।

UAE

डायरेक्ट टैक्स फ्री इकोनॉमी की लिस्ट में सबसे पहला नंबर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) आता है। यहां जनता से कोई व्यक्तिगत टैक्स नहीं लिया जाता है। इस देश में इकोनॉमी के संचालन के लिए सरकार अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट (वैल्यूएडेड टैक्स) और कई चार्ज लेती है। वैसे तो यूएई ऑयल और टूरिज्म सेक्टर में भी काफी मजबूत है, जिसकी वजह से यहां की जनता को इनकम टैक्स में राहत मिलती है।

बहरीन

बहरीन के निवासी भी सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। यहां भी

सरकार डायरेक्ट टैक्स की जगह अप्रत्यक्ष करों और अन्य शुल्कों पर निर्भर है। कहा जाता है कि इस तरीके से देश की इकोनॉमी में भी रफ्तार आती है और यह बिजनेस-स्टार्टअप के लिए भी काफी अच्छा अवसर पैदा करता है।

कुवैत

टैक्स-फ्री देशों (Tax Free Countries) की लिस्ट में कुवैत का नाम शामिल है। कुवैत पूरी तरह से ऑयल से होने वाली इनकम पर वेस्ट इकोनॉमी है। यहां जनता से कोई व्यक्तिगत टैक्स नहीं लिया जाता है। चूँकि, कुवैत की इनकम का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात (Oil Export) से आता है। इस वजह से यहां सरकार जनता से डायरेक्ट टैक्स नहीं लेती है। टैक्स-फ्री देश होने के बावजूद कुवैत की इकोनॉमी काफी मजबूत है।

सऊदी अरब

सऊदी अरब की जनता भी एक रुपये का डायरेक्ट टैक्स नहीं देती है। सऊदी अरब की सरकार ने डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को खत्म कर दिया है। यहां अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू है जो इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करता है। दुनिया की समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में सऊदी अरब का नाम शामिल है।

द बहमास

वेस्टन हेमिस्फीयर में मौजूद द बहमास भी टैक्स फ्री देश है। द बहमास को टूरिज्म के लिए हेवन यानी जन्मत कहा जाता है। चूँकि यहां टूरिज्म सेक्टर काफी मजबूत है, इस वजह से यहां की सरकार जनता से कोई टैक्स नहीं लेती है।

रामनगरी से जुड़े हाईवे घोषित होंगे ग्रीन रूट, चलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन, डीजल गाड़ियां होंगी बैन

परिवहन विशेष न्यूज

अयोध्या से जुड़े चार हाईवे आने वाले समय में ग्रीन रूट घोषित किए जाएंगे। यहां से प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे।

अयोध्या। प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन एल वेक्टरेश्वर लू ने बताया कि अयोध्या से जुड़े चार हाईवे आने वाले समय में ग्रीन रूट घोषित किए जाएंगे। यहां से प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे। डीजल वाहनों को धीरे-धीरे हटा दिया जाएगा। 500 करोड़ से 120 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। अनुबंध की नीति के तहत 5000 अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन किया जाएगा।



प्रमुख सचिव शनिवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम ने पहले से 100 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी कर चुका है। ग्रीन रूट पर डीजल वाहनों का संचालन बंद करने से पहले उन मार्गों पर जितने यात्री चलते हैं, उनके लिए

इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रबंध किया जाएगा। अनुबंध के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के लिए बेहतर रूट और बस स्टेशन दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन उपलब्ध कराने के साथ परिवहन निगम के अफसर सुपरविजन करेंगे। इन सुविधाओं के लिए जो परिवहन

निगम को ज्यादा शुल्क देगा, उसे रूट उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रदेश में 13,000 यात्री व 12,000 स्कूल बसों में हैं खाभियां: प्रमुख सचिव

प्रमुख सचिव के अनुसार प्रदेश में 13,000 यात्री और 12,000 स्कूल बसों में अलग-अलग तरह की खाभियां हैं। इन सबका ब्योरा वाहन पोर्टल पर दर्ज है। इसका जिलावार विवरण निकालकर मुख्य सचिव मनोज सिंह की ओर से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पहले संवाद किया जाएगा, फिर कार्रवाई होगी। अपेक्षा रहेगी कि अवैध वाहनों को उनके स्वामी वैध की श्रेणी में लाएं, नहीं तो स्क्रेप सेंटर में भेजवाने के लिए तैयार रहें। अवैध वाहनों का संचालन किसी भी सूत्र में सड ?क पर नहीं होने दिया जाएगा।

मूल्य वृद्धि पर नवीन बाबू का भाषण योग्य नहीं: दिलीप मोहंती

मनोरंजन सासमल, स्टेटे हेड उड़ीशा

भुवनेश्वर: नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजे सरकार ने अपने 25 साल के शासन के दौरान ओडिशा को किसी भी क्षेत्र में स्वशासित राज्य नहीं बनाया है। ओडिशा राज्य विशेषकर दैनिक खाद्यान्न के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। इसके लिए पूरी तरह से बीजे के शासन काल में शुरू किये गये अलहु मिशन की विफलता जिम्मेदार है। इसी तरह बीजेजे अपने लंबे शासनकाल में एक भी नया कोल्ड स्टोर नहीं बना पाई है। प्रदेश प्रवक्ता श्री दिलीप मोहंती ने कहा कि वेतन वृद्धि के मुद्दे पर वर्तमान विपक्षी दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन बाबू का भाषण योग्य नहीं है और उसी मुद्दे पर बीजेजे पार्टी का भाषण बहुत हास्यास्पद है। इसी तरह चिट्ठी लिखकर अपने से दोष उतारने की नवीन बाबू की पुरानी आदत थी, जो अब भी जारी है। दूसरी ओर, डेड महीने से भी कम समय में सत्ता संभाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी कैप की समस्याओं के प्रति बेहद सजग और सतर्क हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागीय मंत्री श्री कृष्णचंद्र पोटे ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए विभागीय अधिकारियों को कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। श्री मोहंती ने कहा कि राज्य सरकार शिविर की समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम राज्य की जनता देखेगी।



पुरी-अनुगुल पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई



मनोरंजन सासमल, स्टेटे हेड उड़ीशा

भुवनेश्वर: पुरी-अनुगुल पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। बताया गया है कि मालतिपतपुर और हुलहुलवा पोल के बीच ट्रेन से आग लग गयी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ट्रेन की ब्रेक बार्डिंग गराड़ गई थी और मामूली आग लग गई थी। जब लोगों ने ट्रेन के पीछे इंजन से धुआं निकलता देखा तो ट्रेन रुक गई। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खबर मिलते ही रेलवे स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आग देखकर यात्री घबरा गया। आग क्यों और कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है।

उद्यमिता से उज्ज्वल भविष्य की और भारत : कश्मीरी लाल

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

जम्मू। जैविक उद्यमिता आधारित स्वरोजगार के मॉडल से भारत के युवाओं को एक नयी दिशा प्राप्त हो सकती है ऐसा अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल जी ने आज जम्मू कश्मीर स्वदेशी जागरण मंच प्रांत के दो दिवसीय विचार वर्ग के शुभारंभ करते हुए कहा। उन्होंने तमिलनाडु के शिवकाशी के उद्यमी शनमुगम का उदाहरण देते हुए कार्यक्रमों को प्रेरित किया। उद्यमपुर स्थित कलाहाडी फैक्ट्री के शुभमशर्मा को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया ऐसे ही आचार बनाने से जुड़ी युवा महिला उद्यमी प्रतीक्षा ने कार्यक्रम को संबोधित किया और बताया कि उन्होंने कितनी ही बहनो को इस प्रकल्प में सम्मिलित किया हुआ है और रोजगार प्रदान कर रही है। डायरेक्टर हौंडक्राफ्ट्स जम्मू श्री सूज रक्कवाल ने उद्यमियों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। मंच ने आह्वान किया कि वे इस मानसिकता को बदलें कि नौकरी ही रोजगार है। देश में कुल 8 से 9% ही सरकारी नौकरी है। युवा इस चुनौती का समाधान स्वयं का



उद्यम-रोजगार, स्टार्टअप के माध्यम से कर सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्रीय अधिकारी प्रो० आशुतोष, पंजाब प्रांत संगठक विनय जी, प्रांत संयोजक श्री विपिन जी, सह संयोजक डा० मुनीश जी, महानगर संगठक सुनील जी, प्रांत संपर्क अजय चंदेल, विजय जौहर, यशदेव, महानगर संयोजक रवि जी सह संयोजक नरेश जी आदि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रांत महिला प्रमुख, अनीता जी और सह प्रमुख दीपाली जी भी दो दिवसीय कार्यशाला में सम्मिलित हुईं।



आर जी एच एस की डोर स्टेप डिलेवरी के प्रति ई पी फार्मा स्टोर उदासीन, प्रतिकूल शर्तों के कारण बनानी पड़ी दूरी

- विभाग की कथनी और करनी में असमानता से दवा विक्रेताओं में भारी रोष व्याप्त - अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, आगामी दिवसों में समस्याओं का त्वरित निस्तारण नहीं किया गया तो, लाभाधारियों को दवा मिलने में होने वाली असुविधा के लिए राज्य सरकार स्वयं होगी जिम्मेदार।

परिवहन विशेष अनुप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। राज्य सरकार के ऐम ओ यू के अनुसार 21 दिन में भुगतान करने का दवा अब फेल होता नजर आ रहा है। नतीजन 4 माह में राजस्थान के 4500 दवा विक्रेताओं के 600 करोड़ से अधिक के बकाया भुगतान की अब पूरा जग मोग उठने लगी है जिसके चलते दवा विक्रेताओं में भुगतान नहीं होने के कारण भारी रोष व्याप्त है।

प्रादेशिक आजीएसएच अधिकृत दवा विक्रेता समिति के उपाध्यक्ष सुनील भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया की राज्य सरकार ने राज्य के सेवारत-सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए

पायलट प्रोजेक्ट के तहत डोर स्टेप डिलीवरी (कर्मचारी के घर तक दवा पहुंचाने) की घोषणा की थी। उन्ही घोषणा की शर्तों में पोर्टल पर बिल रिजेक्शन के डर से अधिकतर केमिस्ट योजना को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष सुनील भारद्वाज बताते हैं कि डीएसडी यानी डोर स्टेप डिलीवरी योजना में अजीबों गरीब शर्तें हैं, इसमें दवा व्यापारियों को सरकार से पैसे डूबने का डर है। जबकि आरजीएचएस में जुड़ने के लिए 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी ली गई थी। अब दोबारा होम डिलीवरी की सेवा योजना में दवा दुकानदारों से फिर से 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी मांगी जा रही है। इधर केमिस्टों का कहना है कि पहले से तीन माह में केमिस्टों के 600 करोड़ रुपए आरजीएचएस में अटके पड़े हैं। और प्रदेशभर में अब तक सरकार से 2 अरब से ज्यादा रुपए भुगतान नहीं हो पाए हैं। साथ ही DSD में पोर्टल पर पच्ची स्वीकृत कर ली तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, सब्सिड्यूट नहीं दे सकते, लिखी गयी सभी दवाई उपलब्ध करवाने की बाध्दता, पेनेल्टी जैसी शर्तें भी शामिल हैं। साथ ही इस योजना में सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आरजीएचएस पोर्टल पर अपनी एसएसओ



आईडी के जरिए परामर्श पच्ची अपलोड करनी होती है। पच्ची में जिस ब्रांड की दवा लिखी है, उसी ब्रांड की दवा देनी भी होगी। यदि दूसरा मानी ब्रांड दे दिया तो केमिस्टों का बिल रिजेक्ट किया जा रहा है। दूसरा दुकानदारों ने पच्ची पोर्टल से स्वीकृत कर ली तो अब वे उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह कैंसर की तीन लाख की दवा जोड़ी हुई, इंडियन ब्रांड 14 हजार की नहीं जोड़ी। वही आरजीएचएस योजना में कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने वाली दवा लिनपार्जा 3 लाख रुपए की है और इस दवा को योजना में जोड़ा हुआ है, जबकि दूसरी ओर इंडियन ब्रांड इसी सांठ की दवाइयों को नहीं जोड़ा गया है। इसी तरह कई महंगी दवाइयों को जोड़ा जाना एवं उसी घटक की कम कीमत की दवाइयों को नहीं जोड़ा जाना राज्य सरकार के

लिए शुद्ध नुकसान है। जिसके चलते केमिस्टों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में सरकार किसकी गलती की वजह से जान बूझकर ये घाटा झेल रही है? जबकि इंडियन ब्रांड सही नहीं है तो इसे मार्केट में क्यों अप्रुव किया गया।

उपाध्यक्ष भारद्वाज बताते हैं कि करीब ढाई साल से रिजेक्शन और डिडक्शन के बिलों का जानबुझ कर निस्तारण नहीं किया जा रहा है, उसमें भी राजस्थान के केमिस्टों का करोड़ों रुपया अटका हुआ पड़ा है। कुछ इन्हीं अति गम्भीर कारणों के चलते प्रदेशभर के सभी केमिस्टों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। इसी कारण आरजीएचएस के लाभाधारियों को समय पर दवाईयों की आपूर्ति नहीं होती है। और पच्ची में कोई छोटी मोटी कमी रह जाय तो दुकानदार लाभाधारियों को दवाई का मना कर देता है जिसके चलते रोगी डॉक्टर और दवा विक्रेता के बीच चक्कर काट काट करके परेशान होता रहता है। अब इस समस्या पर राज्य सरकार शीघ्रतापूर्वक ध्यान देकर उक्त मामले को जल्द से जल्द निस्तारण भी करें ताकि रोगियों को आर जी एच एस योजना का सही तरीके से पूरा पूरा लाभ मिले जिससे सरकार की योजना का सफलताम संचालन हो सके।

दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार द्वारा माह भारत पर आधारित नाट्य पर चर्चा हुई



जगदीश सीरवी मलकाजगीरी मेडवल बैडिकल भारत

हरिद्वारबाद: सिकंदराबाद स्थित के जे आर गाडन में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार द्वारा माह भारत पर आधारित नाट्य र चक्रव्यूह पर विचार विमर्श किया और नवरात्रि पर्व पर यह नाट्य र चक्रव्यूह पर ग्राउंड कि चर्चा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन' स्वामी विवेकानंद एवं महर्षि अरविन्द के सेवा दर्शन से

प्रभावित होकर 'सेवा, साधना, सम्बोधित' के भाव से कुष्ठ पीडित बन्धुओं की मरहम पट्टी से प्रांरम्भ किया गया। समाज के सबसे पृथित, उपेक्षित एवं पशुवत् जीवन जीने को बाध्य कुष्ठ रोगियों एवं उनके परिवार को सेवा के लिए एम, वचन, कर्म से कृत संकल्प 'दिव्य प्रेम सेवा मिशन' की स्थापना 12 जनवरी 1997 को डॉ. आशीष गौतम द्वारा चण्डीघाट, हरिद्वार से प्रांरम्भ की गई

नाट्य र चक्रव्यूह में विचार विमर्श पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी माध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सुभाष अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मंत्री पाली एवं कोरेमुला बडेर अध्यक्ष कालुराम काग मुचिवा डायराम लचटा, शान्ति लाल सुथार, मनोज भाई, सन्तोष भाई व गणमान्य समाज बन्धु उपस्थित रहे (छाया विवरण जगदीश सीरवी)

कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष पर शहीदों की याद में विशाल वृक्षारोपण



परिवहन विशेष अनुप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। लायंस क्लब भीलवाड़ा के अध्यक्ष लायन आरपी बन्दवा ने बताया की लायंस क्लब भीलवाड़ा एवं लायंस क्लब भीलवाड़ा रूबी के संयुक्त तत्वाधान में पीडीजी, पीएमसीसी लायन अरविंद शर्मा, पीडीजी, पीएमसीएस लायन दिलीप तोषनीवाल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लायन श्याम सुंदर मंत्री के सानिध्य में रीजन चेयरमैन लायन राकेश पणारिया के सहयोग से लायन ओपी काबरा एवं लायंस क्लब रूबी अध्यक्ष लायन मधुकाबरा के

द्वारा अजय सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 570 पौधे जिसमें औषधिय, फलदार, छायादार एवं डेकोरेटिव पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में माइक्रो कैबिनेट चेयरपर्सन लायन मंजू पोखरना, लायंस क्लब भीलवाड़ा स्टार के अध्यक्ष अंकुश जैन, लायन भूपेश सामर, विनोद जैन, मुकेश कोठारी, रूबी क्लब की सचिव सुधा जैन व कोषाध्यक्ष ममता शर्मा एवं डायरेक्टर निखिल काबरा आदि उपस्थित थे।

कारगिल विजय दिवस, भारतीय सेना के अद्वितीय साहस और शौर्य का प्रतीक

डॉ उमेश शर्मा

आगरा। कारगिल विजय दिवस, भारतीय इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमारे वीर जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान की कहानी बयां करता है। यह दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन उन वीर सपूतों का समर्पित है, जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की और पाकिस्तान की सेना एवं आतंकवादी घुसपैटिएर को मुंहतोड़ जवाब देकर भारतीय क्षेत्र से बाहर खदेड़कर भगा दिया।

कारगिल विजय दिवस की जित की 'रजत जयंती' के अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उमेश शर्मा ने कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर अपने अदम्य साहस से दुश्मन को धुल चटाने वाले सभी वीरों जवानों को शत-शत नमन करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अद्वितीय साहस और शौर्य का प्रतीक है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हमारे जवान किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस दिन हम सभी को उन वीर जवानों का नमन करना चाहिए। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की और हमें सुरक्षित रखा। यह विजय दिवस हमारे दिलों में देशभक्ति की भावना को और प्रबल बनाता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी को अपने देश की रक्षा और सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।

एडवोकेट अरविन्द पुष्कर ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय है। कारगिल विजय दिवस हमारे सैनिकों के बलिदान और देशभक्ति की मिसाल है। कारगिल युद्ध में बहुत सी कठिनाइयाँ आयी क्योंकि कारगिल युद्ध भौगोलिक और जलवायु दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद कठिन था। भारतीय सैनिकों को दुश्मन से ऊंचाई पर बैठकर लड़ना पड़ा, जहाँ से पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी घुसपैटियों का

गोलाबारी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, बर्फौली हवाएं, कठिन रास्ते और कम ऑक्सीजन के स्तर ने भारतीय जवानों के सामने और भी चुनौतियाँ खड़ी कर दी थी लेकिन हमारे वीर जवानों ने इन सभी कठिनाइयों को परास्त करते हुए दुश्मन को खदेड़ दिया और लगभग 60 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की, इस युद्ध में 527 भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 1050 से अधिक घायल हुए। इन वीर जवानों के साहस और बलिदान को आज भी याद करता है और सम्मानित करता है। कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी वीरों को बारम्बार नमन।

एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ने कहा, कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और असाधारण पराक्रम के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा सम्मान प्रकट करने का अवसर है। वर्ष 1999 में कारगिल की चोटियों पर भारत माँ की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले प्रत्येक सैनिकी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और उनकी पावन स्मृति में नमन करता हूँ। कुझे विश्वास है कि सभी देशवासी उनके त्याग और शौर्य से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। देश हमेशा कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बहादुर सैनिकों के बलिदान को याद रखेगा। यह विजय दिवस मातृभूमि के कण-कण की रक्षा की। भारत माता के वीर सिपाहियों ने अपने त्याग व बलिदान से इस वसुंधरा की न सिर्फ आन, बान और शान को सर्वोच्च रखा बल्कि अपनी विजित परंपराओं को भी जीवंत रखा। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर मैं सभी वीर सेनानियों का



स्मरण करता हूँ। आपके अदम्य साहस, वीरता और बलिदान से ही कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा पुनः गर्व से लहराया। देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के आपके समर्पण को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। समाजसेवी पंकज जैन ने कहा, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर हम 1999 के युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों की अदम्य भावना और साहस को याद करते हैं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वीरता और देशभक्ति ने सुनिश्चित किया कि हमारा देश सुरक्षित रहे। उनकी सेवा और बलिदान हर भारतीय और हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। कारगिल युद्ध का आरंभ मई 1999 में हुआ जब भारतीय सेना को पता चला कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी घुसपैटिएर कारगिल जिले के महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर चुके हैं। ये घुसपैटिएर भारतीय क्षेत्र में लगभग 4-5 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके थे और ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 श्रीनगर-लेह मार्ग को

खतरा उत्पन्न हो गया था। इस ऑपरेशन का नाम विजय रखा गया था। भारतीय सेना ने इस घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया और पाकिस्तान की सेना एवं आतंकवादी घुसपैटिएर को भारतीय क्षेत्र से बाहर खदेड़कर भगा दिया। हालांकि पाकिस्तान बार बार आतंकवाद और छत्र युद्ध का सहारा लेकर अशांति फैलाने की कोशिश करता है और वहीं, भारत हमेशा शांति स्थापित करता है। पाकिस्तान ने जब भी कुछ नापाक कोशिश की, उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है लेकिन पाकिस्तान ने खुद से कोई सबक नहीं लिया है। वह आतंकवाद और छत्र युद्ध का सहारा लेकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने जब भी कोई दुस्साहस किया, उसे हार का सामना करना पड़ा। यह देश हमेशा हमारे वीर जवानों का श्रणी और आभारी रहेगा। कर्तव्य की राह पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को शत शत नमन एवं श्रद्धांजलि।

फ्रॉलिम निर्माता सावन चौहान ने कहा कि आज हम कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के गवाह बने हैं। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर है। यह विजय दिवस करोड़ों देशवासियों के सम्मान के विजय का दिन है। कारगिल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे देश की सुरक्षा में लोग सैनिक किस प्रकार अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। यह दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने वीर जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर अपने अदम्य साहस से दुश्मन को धुल चटाने वाले सभी वीरों जवानों को शत-शत नमन और अतुलनीय साहस और शौर्य का परिचय देते हुए भारत माँ की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि, शत-शत नमन, जय हिन्द ! जय भारत !